मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | ग्वालियर, रविवार 04 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-173, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

पशुधन और दुग्ध उत्पादन से आएगी गौपालकों के घरों में समृद्धि : केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह

नये कानूनों के मूल में न्याय है, दंड नहीं

एक सत बुलेटिन, भोपाल

केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पशुधन (लाईव स्टॉक) और दुग्ध उत्पादन देश के किसानों और गौवंश पालकों की समृद्धि का प्रमुख आधार है। पशुधन जितना होगा, उतनी ही होगी समृद्धि। देश के किसानों और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है। पशुधन से दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादन से ही गौपालकों के घर समृद्धि आती है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों और पशुपालकों की आय का बड़ा जरिया है। केंद्र सरकार देश में दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए पशुपालकों को कई प्रकार की सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि भोपाल में हुआ यह विशाल गौपालक सम्मेलन मध्यप्रदेश में हो रही श्वेत क्रांति का एक शुभ संकेत है। सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं एक गौपालक हैं, उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश पूरे देश में दुग्धोत्पादन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने प्रदेश के सभी गौपालकों से मप्र में प्रतिदिन 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का बड़ा लक्ष्य लेकर चलने की अपील करते हुए कहा कि सब मिल-जुलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, तभी यह लक्ष्य हासिल होगा। मंत्री श्री शाह शनिवार को भेल दशहरा मैदान में आयोजित विशाल राज्य स्तरीय गौ-पालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।



एमओयू भी हुआ

भोपाल में मोरवन प्रोजेक्ट के तहत नगर वन विकसित करने कृभको एवं म.प्र. बॉयोडायवर्सिटी बोर्ड के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर परस्पर आदान-प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य भोपाल में हरित क्षेत्र का विस्तार करने के साथ जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और नागरिकों के लिए बेहतर प्राकृतिक वातावरण विकसित करना है। नगर वन के विकास से स्थानीय जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा तथा शहर में हरित आवरण को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में मप्र में वर्तमान में मनाये जा रहे कृषक कल्याण वर्ष 2026 (बलराम कृषि महोत्सव) पर केंद्रित लघु फिल्म तथा 'मप्र में दुग्ध क्रांति का सूत्रपात' विषयक एक आकर्षक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

प्रदर्शनी का शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि आज यहां न्याय संहिता प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजी दौर के कई कानूनों को समाप्त कर अपनी न्याय संहिता लागू की है। हमारी न्याय व्यवस्था की पहचान कभी तारीख-पे-तारीख से होती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर के बाद 3 वर्ष में दोषी को सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। अंग्रेजों ने अपनी सरकार को बचाने के लिए कानून बनाए थे। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता के मूल में न्याय दिलाना है, दंड नहीं। दंड सिर्फ अपराध रोकने के लिए ही है। इससे हर भारतीय के सम्मान की रक्षा होगी। इस नवीन न्याय संहिता से भारतीय न्यायपालिका शीघ्र ही दुनिया का सबसे आधुनिक न्याय तंत्र बन जाएगी।

प्रदेश को दीं कई सौगातें

'सहकार से समृद्धि' की थीम पर केंद्रित राज्य स्तरीय सम्मेलन में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का डिजिटल भूमि-पूजन किया। उन्होंने भोपाल में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से नव निर्मित 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के फमेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट, भोपाल में ही 12.42 करोड़ रुपये से नव निर्मित राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला तथा शिवपुरी जिले में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया।

देश को नक्सलवाद से मिली निजात

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि देश को नक्सलवाद की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल गई है। अब बारी पूरे देश को नशामुक्त बनाने की है। भारत को वर्ष 2029 के अंत तक नशामुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। मंत्री श्री शाह ने नागरिकों से मध्यप्रदेश को 31 दिसम्बर 2029 तक पूर्णतः नशामुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने और इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने की अपील की। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि नशामुक्ति के लिए सभी संभव योजनाएं तैयार की जाएंगी।



दूध उत्पादन में अब देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्यप्रदेश : सीएम डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नई दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि देश का अधिकतम दुग्ध उत्पादन म.प्र. की धरती पर हो। उन्होंने कहा कि आज स्वयं केंद्रीय सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में यहां अद्भुत राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रदेश में 80 लाख से अधिक गौपालकों का विशाल समृद्ध परिवार है। राज्य सरकार ने गरीब युवा महिला और नारी शक्ति के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसान कल्याण वर्ष में हमने 17 विभागों को एक साथ जोड़ा है। किसानों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने सभी तरह के प्रयास शुरू किए हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि मेले, कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी, उन्नत कृषि के उपाय किसान भाइयों को बताए जा रहे हैं। किसान भाइयों की आय गौपालन, दूध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्य पालन से बढ़ाने के प्रयास किया जा रहे हैं। किसानों की सबसे अधिक आय दूध उत्पादन से होती है। मध्यप्रदेश दूध उत्पादन में अब देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश के हर गांव-कस्बे की सभी दुग्ध सहकारी समितियों को और भी सशक्त करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इस दिशा में प्रदेश में कई नवाचारी कदम उठाये जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

ई-चालान नहीं भरा तो जब्त होगी गाड़ी



एजेन्सी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में लंबित ट्रैफिक ई-चालान की वसूली के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब बकाया चालान वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा और उनकी ऑनलाइन सेवाएं व आरसी रिन्यूअल रोक दिए जाएंगे। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि बकाया ई-चालान वाले वाहनों की रैंडम जांच की जाए और चालान नहीं भरा मिलने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बैंच ने कहा कि अधिकारियों को ई-चालान वसूली के लिए जमीन स्तर पर काम करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में इस बात पर सख्ती के साथ जोर दिया है कि सडकों पर रैंडम चेकिंग की जाए और अगर किसी वाहन पर पुराना ई-चालान बकाया मिलता है, तो गाड़ी को तुरंत जब्त कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बकायेदार वाहनों की ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाए।

जब तक जुमार्ना नहीं भरा जाता, तब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का रिन्यूअल, डुप्लीकेट आरसी जारी करना और पता अपडेट करने के अनुरोध पर रोक रहेगी। इसके अलावा जब तक सभी पेंडिंग चालान पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते, तब तक गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।

पीएम मोदी ने हरियाणा भाजपा विधायकों से की मुलाकात



एजेन्सी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हरियाणा के सभी भाजपा विधायकों से मुलाकात की और प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर उनका फीडबैक लिया। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से दी। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता तक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरचाना गुप्ता, राज्य सरकार के मंत्री और पार्टी के विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने विधायकों के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद किया और जनता से जुड़े मामलों को लेकर उनके अनुभव और सुझाव जाने। इस दौरान जनसेवा को और प्रभावी बनाने तथा सरकार के कामकाज में जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और भाजपा विधायक हरियाणा भवन से इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। सामूहिक रूप से इलेक्ट्रिक बस से प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की पहल ने स्वच्छ परिवहन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान हरियाणा के जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और जनता से जुड़े विषयों की जानकारी साझा की।

श्री सिटी में हादसे के बाद रेस्क्यू जारी

फार्मा कंपनी में बॉयलर फटा 5 की मौत:10 गंभीर घायल

एजेन्सी, तिरुपति

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री सिटी की एक फार्मा कंपनी में बॉयलर फट गया। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। धमाकों के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। धमाका इतना तेज था कि बिल्डिंग का हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया।

सत्यवेडु मंडल में हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी सर्विस टीमें मौके पर पहुंची और राहत-बचाव का काम शुरू किया। एक अधिकारी के मुताबिक, बॉयलर फटने की सही वजह अभी पता नहीं चली है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि हादसा तकनीकी खराबी, सुरक्षा व्यवस्था में चूक, संचालन संबंधी लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ। अधिकारियों ने अभी सभी मृतकों की पहचान और हादसे की पूरी जानकारी जारी नहीं की है। बचाव अभियान और घायलों की मेडिकल जांच पूरी होने के बाद मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि होने की उम्मीद है।



राज्य में यह पिछले एक साल में हुआ एक और बड़ा औद्योगिक हादसा है। इसी साल जून में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में पिघला हुआ स्टील ले जा रहा लैडल टूट गया था। इसके बाद आग में 8 कर्मचारियों की मौत हुई थी।

2023 में 28 जीते थे, इस बार कुल 85 मेडल, टैली में चौथा स्थान

एशियाड में भारत को 21 गोल्ड, दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

एजेन्सी, नई दिल्ली

भारत ने एशियन गेम्स में 21वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से हराया। शनिवार को भारत ने मेंस क्रिकेट, आर्चरी, गोल्फ और कुश्ती में भी 1-1 गोल्ड जीता। भारत अब 21 गोल्ड सहित कुल 85 मेडल के साथ टैली में चौथे स्थान पर आ गया है। भारत इस बार 21 गोल्ड सहित कुल 85 मेडल जीते। यह एशियाड में भारत का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2023 में भारत ने 28 गोल्ड सहित 106 मेडल जीते थे।



भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के डबल गोल

फाइनल मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने डबल गोल किए। उन्होंने 11वें और 57वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए। हरमनप्रीत के अलावा, जुगराज 23वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर, 42वें मिनट में हार्दिक ने पेनल्टी स्ट्रोक पर और 54वें मिनट में शिलानंद ने फील्ड गोल किया। मलेशिया की ओर से इकलौता गोल शेलो सिल्वरियस ने 14वें मिनट में दागा। उन्होंने फील्ड गोल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहली बार लगातार दो एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी का गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स के एक ही संस्करण में पहली बार भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है।



अंतिम गोल्ड मेडल मैच में 0-2 से पिछड़ी

महिलाओं के 53 किग्रा फाइनल में जापान की मोए कियोका ने शुरूआत में ही अंतिम पंघाल का लेग टेकडाउन कर उन्हें मैट से बाहर किया और एक अंक हासिल किया। इसके बाद भी दोनों के बीच ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। अंतिम ने लेग अटैक की तीन बार कोशिश की, लेकिन कियोका हर बार बच निकलीं। अंतिम को पैसिविटी के लिए चेतावनी के बाद कियोका को एक और अंक मिला। पहले पीरियड के बाद कियोका 2-0 से आगे हैं।

लोगों की पहुंच आसान नहीं, सिर्फ आंकड़े दे रहे गवाही

जबलपुर के 272 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर सवाल

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर



जिले में लोगों को घर के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 272 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित होने का सरकारी आंकड़ा सामने आया है। लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2025 तक मध्यप्रदेश में 12,346 और जबलपुर जिले में 272 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दर्ज थे। संख्या के लिहाज से जिले में नेटवर्क बड़ा है, लेकिन अब सवाल इन केंद्रों की वास्तविक पहुंच और उपयोगिता का है। आम नागरिकों के लिए यह जानना कितना आसान है कि उसके घर के पास कौन सा केंद्र है, वहां कौन-कौन सी सेवाएं मिलती हैं और स्वास्थ्यकर्मी किस समय उपलब्ध रहते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंच के दायरे में लाना है। इनके जरिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सामान्य बीमारियों के उपचार, टीबी देखभाल, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल, प्राथमिक आपात सहायता, दवाएं और जांच जैसी सेवाओं का विस्तार किया जाना है। ऐसे में 272 केंद्रों की मौजूदगी का लाभ तभी प्रभावी रूप से मिल सकता है, जब लोगों को इनके स्थान, समय और उपलब्ध सेवाओं की स्पष्ट जानकारी हो। स्टाफ और नियमित संचालन से तय होगी उपयोगिता किसी केंद्र का संचालन केवल भवन या नाम दर्ज होने से सुनिश्चित नहीं होता।

मरीजों के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता, निर्धारित समय पर केंद्र का खुलना, दवाओं का वितरण और जरूरी जांच की सुविधा इसकी उपयोगिता की अहम कड़ी हैं। यदि किसी क्षेत्र में केंद्र मौजूद है, लेकिन डॉक्टर, सीएचओ या अन्य स्वास्थ्यकर्मी नियमित उपलब्ध नहीं हैं, तो मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए भी बड़े अस्पताल या निजी क्लीनिक जाना पड़ सकता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और प्रबंधन के साथ आवश्यक दवाओं तथा डायग्नोस्टिक सेवाओं की व्यवस्था का प्रावधान है। जबलपुर के 272 केंद्रों पर इन सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता की नियमित जानकारी सार्वजनिक होने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने केंद्रों पर ओपीडी, दवा वितरण, जांच और स्क्रीनिंग नियमित रूप से हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से संबंधित राज्य और जिला स्तर की जानकारी उपलब्ध है। जबलपुर के संदर्भ में ब्लॉकवार केंद्र सूची, सटीक लोकेशन, उपलब्ध सेवाएं, पदस्थ स्वास्थ्यकर्मी, संचालन समय तथा दवा और जांच की स्थिति जैसी जानकारी जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना उपयोगी होगा। इससे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज 272 केंद्रों और उनकी जमीनी उपयोगिता की तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

भाजपा कार्यालय में बजाए चुनावी वादों के ऑडियो, सिहोरा जिला बनाओं आंदोलन समित जबलपुर पहुंची



■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

सिहोरा को पूर्ण जिला बनाने की मांग को लेकर लक्ष्य सिहोरा जिला आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। समिति ने भाजपा जिलाध्यक्ष रत्नेश सोनकर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश शासन और संगठन के शीर्ष नेतृत्व के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधानसभा चुनाव 2023 की सभाओं में नेताओं द्वारा किए गए जिला निर्माण संबंधी वादों की ऑडियो रिकॉर्डिंग साउंड बॉक्स के जरिए सुनाई गई। समिति ने बताया कि नवंबर 2023 में भाजपा प्रत्याशी संतोष बरकड़े के समर्थन में सिहोरा पहुंचीं तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी भाजपा की सरकार बनने पर जिला निर्माण का भरोसा दिलाया था। समिति सदस्यों ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों की याद दिलाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि सिहोरा लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रहा है और क्षेत्र के लोग नेताओं के आश्वासनों के आधार पर उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में सिहोरा को भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक आधार पर जिला बनाने के लिए उपयुक्त बताते हुए सरकार से प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की। समिति ने कहा कि जिला गठन का विधिवत गजट नोटिफिकेशन जारी होने तक जन-जागरण अभियान जारी रहेगा।

लूटपाट के बाद मूक-बधिर महिला की हत्या

जबलपुर। खितौला थाना क्षेत्र के ग्राम दरौलीकला में घर में अकेली रह रही 55 वर्षीय मूक-बधिर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। महिला के हाथ-पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर हत्या की गई। घटना के बाद घर से दो युवक भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस को आशंका है कि लूटपाट के दौरान विरोध करने पर महिला की हत्या की गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दरौलीकला निवासी संजय राठौर ने बताया कि वह मजदूरी करता है। 2 अक्टूबर को वह गांव में काम पर गया था, जबकि उसके पिता भी काम के सिलसिले में ग्राम केवलारी गए थे। घर में उसकी 55 वर्षीय मां लक्ष्मीबाई अकेली थीं। लक्ष्मीबाई बचपन से ही मूक-बधिर थीं। संजय ने बताया कि सुबह करीब 11.30 बजे वह घर आया था। उस समय उसकी मां घर के अंदर परछी में दीवार से टिककर बैठी थीं। कुछ देर रुकने के बाद वह दोबारा काम पर चला गया। 1.30 बजे मोहल्ले के संदीप बर्मन ने आकर बताया कि उसके घर से करीब 20-25 वर्ष उम्र के दो युवक निकलकर भागे हैं और आशंका है कि वे चोरी करके भागे हैं।

गोरखपुर में फ्लैट पर दबिश, अवैध शराब और प्रतिबंधित हुक्का बरामद

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

भोपाल में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की सनसनीखेज हत्या की वारदात के बाद जबलपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद शहरभर में किराए के मकानों, फ्लैट, डुप्लेक्स, पेइंग गेस्ट और केयरटेकर के रूप में रहने वाले लोगों का सत्यापन एवं संदिग्ध ठिकानों की जांच शुरू की गई है। इसी अभियान के तहत गोरखपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब और प्रतिबंधित हुक्का मिला। पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गोरखपुर सीएसपी एमडी नगोतिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और थाना प्रभारियों ने क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने हाल ही में फ्लैट किराए पर लिया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित फ्लैट की तलाशी ली, जहां अवैध शराब और प्रतिबंधित हुक्का बरामद हुआ। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हिरासत में लिए गए युवक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। उससे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अवैध शराब और हुक्का कहां से लाया गया था तथा उसके संपर्क में और कौन-कौन लोग हैं। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नए किराएदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के साथ ही हॉस्टल, पेइंग गेस्ट और अन्य संदिग्ध ठिकानों पर लगातार चेकिंग करने को कहा गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बस का परमिट वैध नहीं होने पर भी बीमा कंपनी मुआवजे की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं : हाईकोर्ट

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि दुर्घटना के समय बस का परमिट वैध नहीं होने के आधार पर बीमा कंपनी को दुर्घटना पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा देने की वैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता।



न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के आश्रितों को 5 लाख 96 हजार रुपये मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।मामला स्व. रूपनारायण यादव और उनकी पत्नी जानकी बाई के पुत्र एवं दामाद से जुड़ा है। प्रकरण के अनुसार रूपनारायण यादव के पुत्र गुड्डू उर्फ उमेश यादव की मोटरसाइकिल से जाते समय एक बस ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उमेश यादव की मृत्यु हो गई, जबकि उसका दामाद घायल हो गया था। घटना के संबंध में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद मृतक की पत्नी जानकी बाई ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर के समक्ष मुआवजा दावा प्रस्तुत किया। अधिकरण ने सुनवाई के बाद 5 लाख 96 हजार रुपये का मुआवजा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ स्वीकार करते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश दिया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के इस निर्णय को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि दुर्घटना के समय बस मालिक के पास वैध परमिट नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दूसरी ओर, दावेदारों की ओर से अधिवक्ता सुशील त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि दुर्घटना के समय बस मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के साथ अनुबंधित थी। बस मालिक को अलग से परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही बस का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किया था, इसलिए दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए बीमा कंपनी अपने वैधानिक दायित्व से बच नहीं सकती। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने दावेदारों की ओर से प्रस्तुत तर्क को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी की आपत्ति खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बस का परमिट वैध हो या न हो, यदि बस का बीमा है तो बीमा कंपनी दावेदारों के प्रति अपने वैधानिक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह दावेदारों को 5 लाख 96 हजार रुपये की मृत्यु दावा राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करे।

1350 जैन तीर्थयात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन सम्मेद शिखर रवाना

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर



तीर्थयात्रा पर जाते हैं।इस वर्ष यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। इसका कारण यह भी है कि मुनि श्री प्रमाणसागर महाराज इस वर्ष श्री सम्मेद शिखरजी में चातुर्मास कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए यह अवसर धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। तीर्थयात्रियों को विदाई देने मदनमहल स्टेशन पर दिगम्बर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाशचंद जैन, कोषाध्यक्ष सतीश वर्धमान, जैन नवयुवक सभा के पदाधिकारी सहित जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ श्री सम्मेद शिखरजी की यात्रा के लिए 1350 तीर्थयात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन शुक्रवार दोपहर मदनमहल रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। तीर्थयात्रा को लेकर स्टेशन पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं भक्ति भाव में नृत्य करती नजर आईं।विशेष ट्रेन को सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहाणी, पूर्व राज्यमंत्री शरद जैन, जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन, पूर्व विधायक विनय सक्सेना और नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।राष्ट्रीय दिगम्बर जैन युवा महासंघ ने मुनि श्री प्रमाणसागर महाराज की प्रेरणा से 18 वर्ष पूर्व प्रतिवर्ष जैन श्रद्धालुओं को श्री सम्मेद शिखरजी की तीर्थयात्रा पर ले जाने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प के तहत प्रतिवर्ष विशेष ट्रेन से श्रद्धालु

डुमना रोड पर तेज रफ्तार कार पलटी, एयरबैग खुलने से चालक की बची जान

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर



एयरपोर्ट डुमना रोड पर शनिवार शाम चंडी टोला के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार चालक युवक को मामूली चोटें आईं। दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग खुल जाने से चालक गंभीर चोटों से बच गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार शाम करीब 4 बजे कार क्रमांक जीजे-38-बीबी-3178 डुमना एयरपोर्ट की ओर से आ रही थी। चंडी टोला के पास अचानक कार लहराने लगी और कुछ ही पल में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। कार के पलटते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। बताया गया है कि जिस समय कार अनियंत्रित होकर पलटी, उस दौरान सड़क पर कोई दूसरा वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा सहित अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। कार विजय नगर निवासी एक युवक चला रहा था। वह अपने जीजा की कार लेकर डुमना की ओर गया था। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने डुमना रोड पर वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर चिंता जताई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी ली। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

सुदामा चरित्र ने श्रद्धालुओं को किया भावविभोर

जबलपुर। ग्राम फुलर (भीटा) में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस पर कथा व्यास श्रीमद् जगतगुरु नृसिंह पीठाधीश्वर डॉ स्वामी नृसिंहदेवाचार्य महाराज, ने भगवान श्रीकृष्ण एवं उनके परम मित्र सुदामा के चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया। महाराजश्री ने सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार के लिए प्रेम, त्याग और निःस्वार्थ संबंधों का अनुपम उदाहरण है। सुदामा अत्यंत निर्धन होने के बावजूद अपने मित्र श्रीकृष्ण से कभी कुछ मांगने नहीं गए।

मुंबई की चिकित्सा कांफ्रेंस में जबलपुर के मरीज के उपचार का दिया गया प्रस्तुतीकरण

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

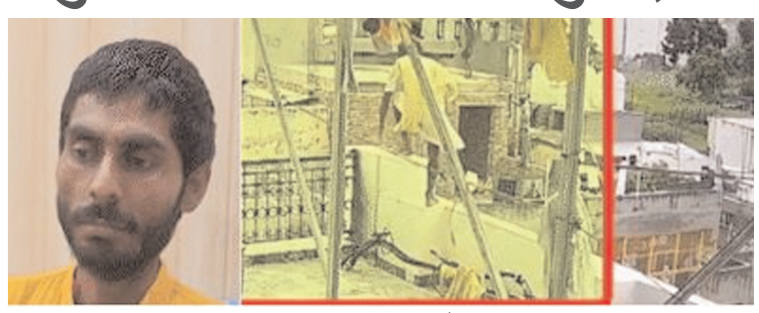


सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ अस्पताल में 70 वर्षीय मरीज की गर्दन की नस में स्टेंट डालकर रक्त प्रवाह बहाल किया गया, जिसके बाद लकवे से प्रभावित अंगों में तत्काल सुधार दिखाई दिया। उपचार के तीन दिन बाद मरीज पैदल चलकर अस्पताल से घर गया। अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक प्रो. अमल कांति सेन ने बताया कि मरीज को शरीर के एक हिस्से में लकवे की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था। जांच के बाद उसकी कैरोटिड धमनी में रुकावट का पता चला। मरीज की स्थिति को देखते हुए प्रभावित गर्दन की नस में कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग की गई और रक्त प्रवाह को सामान्य किया गया। स्टेंट डालने के बाद मरीज ने तत्काल प्रभावित हिस्से के अंगों को हिलाना शुरू कर दिया। जिस आंख को वह पहले बंद नहीं कर पा रहा था, उसे भी बंद करने लगा। उपचार के तीन दिन बाद मरीज पैदल चलकर घर गया। प्रो. सेन ने बताया कि कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग गर्दन की नस में रक्त प्रवाह की रुकावट को दूर करने की आधुनिक उपचार पद्धति है। मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली कैरोटिड धमनी में रुकावट होने पर शरीर के विपरीत हिस्से में लकवे के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई के ग्रैंड हयात में आयोजित क्रिस्प कांफ्रेंस में इस मरीज की बीमारी, उपचार और स्टेंटिंग के परिणाम का चिकित्सकीय प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

सीसीटीवी और फॉरेंसिक साक्ष्यों की हो रही जांच

रसिक दुलारी शरण की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी, 50 से अधिक लोगों से पूछताछ

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर



संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य और जबलपुर निवासी दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मथुरा में हुई संदिग्ध मौत की गुत्थी घटना के नौ दिन बाद भी पूरी तरह नहीं सुलझ सकी है। मथुरा पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब तक 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। पुलिस की सात टीमें अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और मृतक के संपर्क में रहे लोगों से मिली जानकारी को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार 25 सितंबर को रसिक दुलारी शरण वृंदावन स्थित गऊ कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से नीचे गिरे थे। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में उनके चौथी मंजिल से गिरने की घटना सामने आई है, लेकिन घटना से पहले की परिस्थितियों और उनके इस कदम के कारणों को लेकर जांच जारी है। पुलिस ने रसिक दुलारी के साथ रहने वाले साधकों, परिचितों और आश्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। उनके साथ बिजली का काम करने वाले मिस्त्री और परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है। जांच अब मांट क्षेत्र स्थित नए आश्रम यमुना विहार कुंज तक भी पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि घटना से पहले और बाद में रसिक दुलारी की गतिविधियों को सीसीटीवी के जरिए ट्रेस किया जा रहा है। घटना के समय गुरु कृपा कुंज के सामने रहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह खाना खा रहा था। तभी अचानक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर आने पर जमीन पर एक साधु घायल अवस्था में दिखाई दिए। इसके बाद कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें निजी वाहन से अस्पताल ले गए। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी यह नहीं बता सका कि उस समय साधु की स्थिति क्या थी। पुलिस इस मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों को जोड़कर घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है। फॉरेंसिक जांच और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के साथ मृतक के मोबाइल व अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने रसिक दुलारी शरण की मौत का मामला एक बार फिर गहराता जा रहा है। घटना को काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी मौत की गुत्थी अनसुलझी हुई है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस ठोस सबूत हाथ नहीं लग सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस इस मामले में बेहद संवेदनशीलता और गहराई से जांच कर रही है। अब तक इस सिलसिले में 50 से अधिक लोगों से लंबी पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ के दायरे में उनके करीबी सहयोगी, पारिवारिक सदस्य, और संपर्क में रहने वाले अन्य लोग शामिल हैं।

न्यूज ब्रीफ

नहीं माने नियम, 3000 का जुर्माना और भैंस जब्त



वार्ड 14 स्थित गायत्री नगर पुल पर भैंस पालकों द्वारा भैंस बांधकर रास्ता जाम किया जा रहा था। भैंस पालक से परेशान होकर क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार शिकायतें नगर निगम में की जा रही थीं, नगर निगम की टीम पहले भैंस मालिक को दो बार सफाई रखने और भैंसे अलग स्थान पर बांधने के निर्देश दिए थे। लेकिन भैंस मालिक श्री नंदकिशोर ने निर्देशों को नहीं माना, जिसके चलते आज नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3000 का जुर्माना लगाया और एक भैंस को जब्त किया और उन्हें नगर निगम द्वारा संचालित आदर्श गौशाला भेज दिया है। वार्ड क्रमांक 14 में भैंस पालकों द्वारा गोबर को नाले में फेंका जा रहा था, साथ ही भैंसों को भी नाले के मार्ग के बीच में बांध रहे थे, जिसके कारण वहां से निकलने वाले लोगों को वाहन निकालने एवं पैदल निकलने में काफी परेशानी हो रही थी।

आमजन की समस्याओं का शिविर में होगा समाधान



ग्वालियर। *मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2026 रविवार को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ जन जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा सेतु शिविर का आयोजन नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर किया जाएगा। अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत 4 अक्टूबर रविवार को आयोजित सेवा सेतु शिविर में प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा, इस अभियान में पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने सेवा सेतु अभियान के तहत सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।*

जॉब का झांसा देकर महिला से 12.77 लाख की ठगी



ग्वालियर। *ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र में एक महिला को SBI में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 12.77 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी और ऑनलाइन सर्विस सेंटर संचालक समीर रामपुरे ने बैंक अधिकारियों से अपनी अच्छी पहचान होने का दावा किया था। उसकी बातों में आकर महिला ने नौकरी के लिए जरूरी दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी भी उसे दे दी। आरोप है कि जून 2025 से जुलाई 2026 के बीच समीर ने नौकरी लगवाने और अधिकारियों को पैसे देने के नाम पर महिला से अलग-अलग किस्तों में कुल 12 लाख 77 हजार 900 रुपए ले लिए। नौकरी नहीं लगने पर महिला ने रकम वापस मांगी तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया और धमकी देने लगा। शिकायत पर माधौगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माधौगंज हेमसिंह की परेड, एकतापुरी कॉलोनी गली नंबर-6 निवासी 39 वर्षीय रेनू राठौर पत्नी चंद्रभान सिंह राठौर ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोस में समीर रामपुरे 'पद्मा ऑनलाइन सर्विस सेंटर' चलाता है। रेनू वहां फोटो कॉपी और सरकारी भर्ती के फॉर्म भरवाने जाती थीं। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई।*

थाना के सामने व्यापारी को गोली मारी:

हमलावर के परिवार की लड़की के लापता होने से मामला पेचीदा, घायल का भांजा जांच के घेरे में

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



शहर में शुक्रवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। पड़ाव थाना के ठीक सामने स्थित बांके विहारी स्वीट्स एंड नाश्ता सेंटर के संचालक अशोक पाल पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली अशोक की कमर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर दुकान में ही गिर पड़े। वारदात के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पड़ाव थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

परिजनों की मदद से अशोक पाल को सांई बाबा मंदिर के पास स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घटना के बाद इलाके में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। दुकान पर रोज की तरह मौजूद थे अशोक बताया गया कि शुक्रवार दोपहर अशोक पाल अपनी दुकान पर रोज की तरह मौजूद थे। दुकान पर कर्मचारी भी अपने नियमित काम में व्यस्त थे। इसी दौरान पुरानी छावनी क्षेत्र निवासी दिनेश यादव और छोटू यादव कुछ अन्य लोगों के साथ बाइक से वहां पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने दुकान पर पहुंचते ही अशोक पाल से गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने के बाद हमलावरों ने हथियार निकाल लिए और दुकान के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर दुकान के काउंटर तक पहुंच गए और वहीं से अशोक को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। एक गोली अशोक की कमर में जा लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद हमलावर वहां से तेजी से भाग निकले। अचानक हुई फायरिंग से दुकान और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हमलावर किस रास्ते से दुकान तक पहुंचे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए। परिजनों ने आधा दर्जन लोगों पर लगाया आरोप घायल अशोक पाल के भाई प्रकाश उर्फ सोनू पाल ने पुलिस को दिए बयान में पुरानी छावनी निवासी दिनेश यादव और छोटू यादव के नाम बताए हैं। उनका आरोप है कि दोनों आरोपी अपने साथ करीब आधा दर्जन लोगों को लेकर दुकान पर पहुंचे थे। सोनू पाल के अनुसार, आरोपियों ने पहले विवाद किया और इसके बाद अशोक पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

हमले के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात

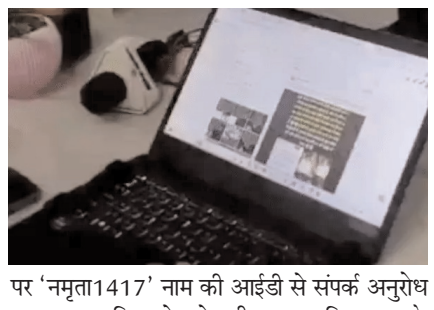
थाने के सामने ही गोली चलने की घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हमलावरों के पास हथियार कहां से आए और वारदात से पहले उन्होंने अशोक पाल की गतिविधियों की कितने समय तक निगरानी की थी।

15 दिन से लापता है हमलावर पक्ष के परिवार की युवती

परिजनों और पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, इस हमले के पीछे एक युवती के लापता होने को लेकर चल रही रंजिश सामने आ रही है। बताया गया है कि आरोपी पक्ष के परिवार की एक युवती करीब 15 दिन पहले लापता हुई थी। आरोपी पक्ष को संदेह था कि अशोक पाल का भांजा युवती को अपने साथ ले गया है। परिजनों के अनुसार, आरोपी पक्ष को यह भी शक था कि अशोक पाल अपने भांजे को शरण दे रहे हैं और उन्हें युवती तथा भांजे के ठिकाने की जानकारी है। इसी संदेह और पुरानी रंजिश को हमले की वजह बताया जा रहा है। हालांकि, युवती के लापता होने और हमले के बीच वास्तविक संबंध की पुष्टि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। गोली की आवाज सुनकर जुटे लोग फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। दुकान के कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों ने घायल अशोक को संभाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर फायरिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं।

नाबालिग बहनों के फोटो-वीडियो वायरल कर बदनाम करने का आरोप

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



ग्वालियर में दो नाबालिग बहनों को सामाजिक माध्यम पर बदनाम करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने 'नमृता1417' नाम से फर्जी सामाजिक माध्यम खाता बनाकर दोनों बच्चियों के फोटो और वीडियो प्रसारित किए।

तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां भी की गईं। इतना ही नहीं, परिवार का पता और बच्चियों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिए गए। इसके बाद परिवार के पास लगातार अनजान लोगों के फोन और संदेश आने लगे। जनकगंज थाना क्षेत्र निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 6 जनवरी से 2 अक्टूबर 2026 के बीच की बताई गई है। संपर्क करने के दो दिन बाद तस्वीरों की गई प्रसारित महिला के अनुसार, 6 जनवरी को उसके सामाजिक माध्यम खाते पर 'नमृता1417' नाम की आईडी से संपर्क अनुरोध आया था। महिला ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके करीब दो दिन बाद अज्ञात व्यक्ति ने उसकी दोनों बेटियों की उनके पिता के साथ खिंची तस्वीरें प्रसारित कर दीं। आरोप है कि तस्वीरों के साथ अश्लील टिप्पणियां की गई और बच्चियों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिए गए। बाद में आसपास के लोगों के माध्यम से महिला को सामाजिक माध्यम पर चल रही इन पोस्ट की जानकारी मिली।

वन्यजीवों के बारे में रोचक जानकारी पाकर अचंभित हुए विद्यार्थी गांधी प्राणी उद्यान में वन्यप्राणी सप्ताह

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



नगर निगम ग्वालियर द्वारा संचालित गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में वन्यप्राणी सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 अक्टूबर 2026 को स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए गांधी प्राणी उद्यान के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें वन्यप्राणियों के संरक्षण, व्यवहार और पर्यावरणीय महत्व की व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराना रहा। भ्रमण के दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 80 छात्र-छात्राओं ने गांधी प्राणी उद्यान का भ्रमण किया। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में मौजूद विभिन्न वन्यप्राणियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्हें वन्यजीवों की जीवनशैली, खान-पान, रहन-सहन, व्यवहार तथा उनके प्राकृतिक आवास के बारे में बताया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को वन्यप्राणियों को लेकर समाज में प्रचलित विभिन्न भ्रांतियों के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया।

युवाओं के लिये ए.आई. पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) यूथविंग टीम कार्यशाला कर्तव्य-2 में मुख्य अतिथि के रूप मं बोलते हुये कैट मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने कहा कि शीघ्र ही एमआईटीएस ग्वालियर में युवा उद्यमियों के लिये ए.आई. की कार्यशाला आयोजित की जायेगी, जिसके माध्यम से व्यवसाय में ए.आई. का उपयेाग कर हम किस प्रकार व्यापार बढा सकते हैं, इसे युवाओं का सिखाया जायेगा। चुनातियों से निपटने के लिये टेक्नोलोजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय और वाटसअप से विजनिस, औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण, नये बनने वाले टेक्नोलोजी हब, ग्वालियर में स्थापित आई.टी.पार्क, रेडीमेट पार्क एवं मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कर एन्सलरी यूनिट एवं व्यापार की संभवनाए तलाशेगे और युवाओं के लिये रोजगार स्थापित करायेंगे।

कैट यूथविंग प्रभारी नीरज चौरसिया ने युवाओं से उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा की। तय हुआ कि महीने में दो कार्यक्रम व्यवयास की जानकारी एवं व्यापार वृद्धि के लिये किये जायेंगे औश्र प्रत्येक मंगलवार को शासकीय जन सुनवाई में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम एवं विभागों की व्यापारिक समस्याओं को लेकर पहुंचेगे ताकि उनका निराकरण कराया जा सके।

चेकिंग अभियान,315 वाहनों के चालान, 1.45 लाख जुर्माना

ग्वालियर। ग्वालियर में पुलिस ने पूरे शहर में दो घंटे का चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 315 वाहनों के चालान कर 1.45 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 61 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए यातायात पुलिस ने आरटीओ को पत्र लिखा है। चेकिंग के दौरान मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पकड़े जाने पर एक युवक ने पूर्व विधायक को फोन किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि नियम तोड़ने पर जुर्माना भरना होगा। कुछ वाहन चालकों ने पुलिसकर्मी रिश्तेदारों से भी सिफारिश कराई, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। तानसेन तिराहे पर तैनात एएसआई सुदेश भिलावी और आरक्षक राजवीर ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका। प्राथमिक जांच में बाइक चोरी की निकली। पुलिस इसकी विस्तृत जानकारी का सत्यापन कर रही है। बाइक को कानूनी कार्रवाई के लिए पड़ाव थाना भेज दिया गया है। काली फिल्म और फर्जी नंबर प्लेट वाली कार जब्त यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका। जांच में कार के चारों शीशों पर काली फिल्म लगी मिली। इसके अलावा आगे की नंबर प्लेट गायब थी, जबकि पीछे की प्लेट पर जानबूझकर टेप चिपकाया गया था। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिलों पर भी कार्रवाई की गई। बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग क्यों जरूरी ग्वालियर पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

12 महीने बाद घटने लगी पैरों की ताकत जीन उपचार के लिए चाहिए 17 करोड़

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

विनय नगर सेक्टर-4 निवासी डेढ़ साल की नीलाक्षी भार्गव दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी रीढ़ की मांसपेशियों के क्षय की बीमारी से जूझ रही है। चिकित्सकों की जांच में उसे एसएमए टाइप-2 होने की पुष्टि हुई है। परिवार के अनुसार, जन्म के बाद करीब 12 से 13 महीने तक बच्ची में बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन 15-16 महीने की उम्र में वह खड़ी नहीं हो पाई। अब उसकी शारीरिक ताकत लगातार कम हो रही है।

परिवार के अनुसार, बच्ची के उपचार के लिए करीब 15 से 17 करोड़ रुपए की जीन उपचार पद्धति की आवश्यकता बताई गई है। इसके लिए परिवार ने सरकार, प्रशासन और आम लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की है। 15-16 महीने की उम्र में खड़ी नहीं हो पाई नीलाक्षी के पिता सौरभ भार्गव ने बताया कि शुरुआती 12 से 13 महीनों तक बेटी सामान्य थी। परिवार को लगा कि कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं, इसलिए नीलाक्षी भी समय के साथ चलने लगेगी। लेकिन 15-16 महीने की उम्र में जब वह खड़ी नहीं हो पाई तो परिवार को चिंता हुई।

पिता के मुताबिक, पहले नीलाक्षी खुद उठकर बैठ जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी शारीरिक ताकत कम होने लगी। अब वह खुद उठकर बैठ भी नहीं पाती है। ग्वालियर में चिकित्सक विजय गुप्ता से परामर्श के बाद सौरभ बच्ची को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लेकर गए। वहां बाल तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकुश ने प्रारंभिक जांच के बाद एसएमए जीन जांच कराने की सलाह दी। जांच की रिपोर्ट करीब 15 दिन बाद आई, जिसमें एसएमए टाइप-2 की पुष्टि हुई।

पालकी शोभायात्रा में महिलाओं ने की मंगल कलश से आगवानी

विमल सागर के जयकारों से गूंजा परिसर, 100 रसों से हुआ पंचामृताभिषेक

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

ग्वालियर के इतिहास में प्रथम बार ऐतिहासिक नगरी पुण्यभूमि पर आज शनिवार को वात्सलय रत्नाकर अचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का 111 वाँ जन्म जयंती श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। पूरा वातावरण गुरु भक्ति में डूबा नजर आया। महोत्सव के अंतिम दिन जैनाचार्य चैत्य सागर महाराज ओर मुनिश्री अनुमान सागर महाराज के सानिध्य में आत्म साधना वर्षायोग समिति तथा सकल जैन समाज ग्वालियर की ओर से दानाओली स्थित दिगंबर बीसपंथी जैन मंदिर से वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर का जन्मोत्सव पर पालकी शोभायात्रा निकाली एवं विनयांजलि सभा आयोजित की गई। पालकी शोभायात्रा में केबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह सम्मिलित हुए।

जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि पालकी शोभायात्रा में जैनाचार्य श्री चैत्य सागर महाराज ओर मुनिश्री अनुमान सागर महाराज के मंगल सानिध्य में आचार्य श्री विमल सागर महाराज की प्रतिमा को पालकी में विराजित संजय सचिन गोधा परिवार ने की। पालकी शोभायात्रा दाना ओली स्थित दिगंबर बीसपंथी चंपाबाग जैन मंदिर से गाजेबाजे के साथ शुरू हुई। जिसमें पालकी शोभायात्रा में सबसे आगे जैन ध्वज पताका आचार्य श्री के



जन्मोत्सव आनंद का संकेत दे रही थी। ध्वज पताका के पीछे बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ गुरुभक्त आचार्य श्री विमल सागर महाराज की प्रतिमा को पालकी अपने कंधे पर लिए हुए चल रहे थे। वही केबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने पालकी में विराजित आचार्य श्री विमल सागर जी के दर्शन कर श्रीफल भेंटकर मंगल आरती उतारी। कैविनेट मंत्री ने पालकी को कंधा दिया। कई जगहों पर शोभायात्रा का जैन सामान के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत एवं आरती उतारी गई।

शोभायात्रा में गूंज रहे भजनों की धुन पर श्रावक एवं श्राविकाएं थिरकते हुए चल रही थीं। महिलाएं केसरिया साड़ी एवं पुरुष सफेद वस्त्रों में अलग रंग में ही नजर आ रहे थे। महिलाओं ने मंगल कलश से आगवानी की गई। महिलाएं डांडिया नृत्य से शोभा बढ़ाई। शोभायात्रा में पालकी चार इंद्र लेकर चल रहे थे। यह पालकी शोभायात्रा दाना ओली से शुरू होकर मोर बाजार, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, गस्त का ताजिया से नई सड़क होती हुई चंपाबाग बगीची पहुंची।

जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि प्रतिष्ठाचार्य पंडित विपिन शास्त्री के मार्ग दर्शन में आचार्य श्री विमल सागर महाराज की प्रतिमा पर कलशों से जलभिषेक अभिषेक किए। वही जैन समाज के लोगो ने वस्त्र धारण कर कलशों में पईनापाल, अनार, मौसमी, सीताफल, केला, आलू बुखार, दूध, घी, दही, सर्व औषाधिका, बुरा, आम के रस आदि 100 रसों से जयकारों के साथ पंचामृतभिषेक किए गए। वही जैन समाज के लोगो ने विनयांजलि सभा आयोजित की गई।

संपादकीय

घोषणा-पत्र गायब!

हमारे देश में दो सबसे प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं-सर्वोच्च अदालत और चुनाव आयोग। अक्सर शीर्ष अदालत चुनाव आयोग के फैसलों, कार्य-प्रणाली और अभियानों में हस्तक्षेप नहीं करती। दलील दी जाती रही है कि वह भी संवैधानिक संस्था है, लिहाजा संविधान की गरिमा और वैधता को समझती है। अलबत्ता सर्वोच्च अदालत आयोग के फैसलों की आधी-अधूरी समीक्षा जरूर करती रही है। सवाल है कि फॉर्म 6 के साथ जो घोषणा-पत्र नत्थी किया गया था, उसे सर्वोच्च अदालत ने अवैध करार क्यों नहीं दिया? आयोग को निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि फॉर्म 6 में कोई भी बदलाव उसके अधिकार-क्षेत्र में नहीं है? संसद और भारत सरकार की स्वीकृति और अधिसूचना के बाद ही चुनाव आयोग कोई बदलाव कर सकता था। अब अचानक 26 सितंबर को आयोग का फैसला सामने आया कि जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हो चुका है अथवा अभी होना है, वहां फॉर्म 6 के साथ घोषणा-पत्र की अनिवार्यता नहीं है। बीती 30 सितंबर को आयोग के साफ्टवेयर तंत्र से ही फॉर्म 6 के साथ वाला घोषणा-पत्र गायब हो गया। कहां गया घोषणा-पत्र..? अब किसने फैसला लिया कि घोषणा-पत्र हटा दिया जाए? क्या यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और दोनों चुनाव आयुक्तों-सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी-का साझा निर्णय है? देश को जानने का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल भी तार्किक लगते हैं कि फॉर्म 6 में अवैध तरीके से बदलाव किसके आदेश से किया गया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को आदेश किसने दिया? कंपनी में किसने मंजूरी दी? हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा-पत्र गायब होने का मुद्दा अभी नहीं उठाया है। घोषणा-पत्र को हटाने अथवा गायब होने का महत्व इसलिए है, क्योंकि लाखों वैध मतदाताओं को बाध्य कर घोषणा-पत्र भरवाए जा रहे थे। सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि यदि मतदाता अपने माता-पिता या दादा-दादी के मतदाता होने की पुष्टि नहीं करता अथवा वह कॉलम नहीं भरता, तो उसे भी मतदाता-सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। फॉर्म 6 के घोषणा-पत्र के जरिए मतदाताओं को झूठ बोलने को भी विवश किया जाता रहा है कि वह पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी मतदान नहीं किया। यह मामला भी शीर्ष अदालत के सामने उठना चाहिए। इंडी गठबंधन की बैठक में प्रख्यात अधिवक्ता एवं सांसद कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया था कि आयोग में आईटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की महानिदेशक सीमा खन्ना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि सीईसी ज्ञानेश को तो 2023 के कानून के मुताबिक कानूनी कवच मिला हुआ है। नतीजतन तय हुआ कि देश भर में सीमा खन्ना के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराई जाएंगी। यह भी विपक्ष के राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा है। बहरहाल फॉर्म 6 के साथ घोषणा-पत्र की बाध्यताएं घोर संवैधानिक क्रूरता और अवैधता की व्यवस्था थी। यदि असहमत दोनों चुनाव आयुक्तों के जरिए इस संबंध में सवाल सार्वजनिक नहीं किए जाते, तो तय था कि फॉर्म 6 का फ्रॉड भी बेनकाब नहीं होता। बहरहाल चुनाव आयोग ने अब भी स्पष्ट नहीं किया है कि फॉर्म 6 के साथ वाला घोषणा-पत्र हटाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया? घोषणा-पत्र के कारण जिनका मताधिकार छीन लिया गया, क्या वह बहाल किया जाएगा? और कब तक यह संभव होगा? जुलाई और सितंबर के बीच ऐसा क्या हुआ कि घोषणा-पत्र अचानक गायब करना पड़ा? उसे हटाने की प्रशासनिक प्रक्रिया का खुलासा भी नहीं किया गया है। यदि घोषणा-पत्र गायब नहीं किया गया है, तो सॉफ्टवेयर पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग देश की जनता को न बताए, लेकिन सर्वोच्च अदालत के सामने तो सच बताना ही पड़ेगा। शीर्ष अदालत की भी अग्नि-परीक्षा होनी है, क्योंकि एसआईआर को अवैध करार देकर उसे हटाने, खत्म करने की मांग याचिका के जरिए की गई है। दिल्ली में जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उनके आधार और पारदर्शिता को चुनौती देते हुए एसआईआर के खिलाफ भी याचिकाएं शीर्ष अदालत के विचाराधीन हैं। बेशक बिहार चुनाव के दौरान शीर्ष अदालत ने एसआईआर को संवैधानिक करार दिया था, लेकिन उसके बाद 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम सूचियों से काट दिए गए हैं।

रासुका के दुरुपयोग पर उठते सवाल

> कफील खान के मामले में भी बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए को अवैध बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों ने कई मौकों पर चिंता जताई है कि पुलिस और जिला प्रशासन अक्सर सामान्य कानून-व्यवस्था के मामलों, राजनीतिक विरोधों, और यहां तक कि स्थानीय विवादों जैसे गोकशी, बिजली चोरी या माफिया मामलों में भी बिना पुख्ता आधार के एनएसए का सहारा लेते हैं। इस कानून का दुरुपयोग रोकने को ठोस उपाय होने चाहिए

देश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के दुरुपयोग पर सवाल उठते रहे हैं। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई फैसले से जाहिर हो गया कि सरकारें किस तरह से इस कानून का इस्तेमाल करके राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दुरुपयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की फजीहत करा दी। संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुल्ला अफरोज की एनएसए के तहत हिरासत को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख का जुमार्ना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें मुल्ला अफरोज के खिलाफ जारी डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागु की बेंच ने कहा कि प्रीवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियाती हिरासत के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा-जुडिशियल कंफेशन, अर्थात न्यायालय के बाहर किए गए कथित कबूलनामे को ही एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुमार्ना लगाते हुए कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को मामले से जुड़ी अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए था। सुनवाई में अदालत ने पाया कि मुल्ला अफरोज के मामले में अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। संभल में नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान हिंसा के आरोप में मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया था।

बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को मुल्ला अफरोज के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार और भाजपा के लिए दोहरा झटका है। पहला तो एनएसए का दुरुपयोग और दूसरा अल्पसंख्यकों के प्रति नजरिया। अल्पसंख्यकों के मामले में सख्ती के भाजपा सरकारों पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में गत अप्रैल में हुए मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में रखने पर गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी अर्थात डीएम रूपम पर पांच लाख रुपए का जुमार्ना लगाया था। यह राशि उनकी सैलरी से काटकर छात्रा को देने का निर्देश दिया गया था। रूपम ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। भाजपा की राज्यों सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग करने के मामलों की लंबी फेहरिस्त है। भाजपा सरकारों को आलोचना पसंद नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अर्थात रासुका (1980) का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाए रखना है। हालांकि विपक्ष, मानवाधिकार कार्यकताओं और कानूनी विश्लेषकों द्वारा केंद्र और विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारों पर राजनीतिक विरोधियों, आलोचकों और प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पिछले साल सितंबर में लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राजस्थान की जोधपुर जेल में डाल दिया गया। सरकार ने कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। देश भर में हुई मोदी सरकार की तीखी आलोचना के बाद केंद्र सरकार ने मजबूर होकर वांगचुक से एनएसए हटा लिया और उन्हें रिहा किया गया। यह वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक प्रकरण में मोदी सरकार की सत्ता की नींव को हिला कर दिया था। वांगचुक ने नीट परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जंतर-मंतर पर 28 जून 2026 से भूख हड़ताल शुरू की थी। तबीयत बिगड़? और 26 दिनों तक चले अनशन के बाद, केंद्रीय मंत्रियों (जेपी नड्डा और डा. जितेंद्र सिंह) के लिखित आश्वासन और सांसदों की अपील पर उन्होंने 24 जुलाई 2026 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपना अनशन समाप्त किया। विडंबना यह है कि जिस वांगचुक पर एनएसए लगाया गया, उन्हीं का अनशन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे का एक बड़ा कारण बना। इसी तरह मणिपुर में पुलिस ने पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम और राजनीतिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लीचेम्बम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मणिपुर के दिवंगत भाजपा अध्यक्ष एस तिकेंद्र सिंह की खिल्ली उड़ाई। 40 वर्षीय दोनों आरोपियों ने फेसबुक पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अलग-अलग पोस्ट कर लिखा था कि गाय का गोबर या गोमूत्र कोविड-19 से बचाव नहीं करते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट के जुलाई 2021 में दिए गए आदेश पर पत्रकार वांगखेम को रिहा किया गया। जबकि राजनीतिक कार्यकर्ता लिचोमबाम इरेंद्रो को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद रिहा किया गया था। एनएसए के दुरुपयोग की सूची में साल 2026 में ही असम में स्वदेशी और भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले का मामला भी है। डोले को काजीरंगा में लक्जरी होटल निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के कारण गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सरकार ने उन पर एनएसए लगा दिया, जिसकी कांग्रेस और अन्य नागरिक संगठनों ने ह्यअसाधारण कानूनों को हथियार बनाकर असहमति दबानेह्ण के रूप में कड़ी आलोचना की थी।

गोलाघाट सत्र न्यायालय ने 29 जुलाई 2026 को उन्हें जमानत दे दी। राजनीतिक दुर्भावना से एनएसए का इस्तेमाल सहारनपुर हिंसा के मामले में 2017-2018 में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर किया गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने आजाद पर एनएसए लगा दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण पर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटा लिया था।

विश्व बदल रहा है, भारत को अपने आर्थिक विकल्प बढ़ाने होंगे

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

विकास दर अर्थव्यवस्था की गति बताती है, उसकी संपूर्ण शक्ति का परिचय नहीं देती। स्थायी आर्थिक शक्ति के लिए बेहतर शासन, तेज निर्णय प्रक्रिया, नवाचार, उत्पादकता, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और वैश्विक बाजारों में भारतीय कंपनियों की मजबूत उपस्थिति जरूरी है। आर्थिक समीक्षा ने भी राज्य की बढ़ी हुई क्षमता और बेहतर शासन को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की प्रमुख शर्त माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की आर्थिकी को संस्थागत क्षमता पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें कि ऊर्जा सुरक्षा इस चुनौती का सबसे संवेदनशील पक्ष है। उल्लेखित है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है।



किसी बड़ी अर्थव्यवस्था की ब्याज दरें वैश्विक पूंजी का रुख बदलने लगें और शक्तिशाली देश की व्यापार नीति विश्व के कई देशों को प्रभावित करने लगे, तब असल परीक्षा हर उस देश के लिए होती है, जिसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाए भी रखना है। भारत भी इन दिनों कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश के सामने यही सबसे बड़ा आर्थिक चिंता का कारण यही है कि उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को अब अपनी गति के साथ अपनी सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ निरंतर मजबूत बनाकर रखा जाए।

वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा ने इसी बदलते परिदृश्य की ओर संकेत करते हुए कहा है कि कोविड के बाद मिली विकास उपलब्धियों को सहज मानकर आगे बढ़ने का समय समाप्त हो चुका है। भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण, वैश्विक ब्याज दरें, पूंजी प्रवाह, आपूर्ति व्यवधान और मुद्रास्फीति जैसे कारक लगातार आर्थिक निर्णयों की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में भारत को व्यापार-अनुकूल व्यवस्था से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा-अनुकूल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। वस्तुतः इसी में भारत की अगली आर्थिक यात्रा का मूल छिपा है।

विकास दर अर्थव्यवस्था की गति बताती है, उसकी संपूर्ण शक्ति का परिचय नहीं देती। स्थायी आर्थिक शक्ति के लिए बेहतर शासन, तेज निर्णय प्रक्रिया, नवाचार, उत्पादकता, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और वैश्विक बाजारों में भारतीय कंपनियों की मजबूत उपस्थिति जरूरी है। आर्थिक समीक्षा ने भी राज्य की बढ़ी हुई क्षमता और बेहतर शासन को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की प्रमुख शर्त माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की आर्थिकी को संस्थागत क्षमता पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें कि ऊर्जा सुरक्षा इस चुनौती का सबसे संवेदनशील पक्ष है।

उल्लेखित है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। समुद्री मार्ग में व्यवधान अथवा कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि का असर परिवहन, उद्योग, बिजली, उपभोक्ता बाजार और मुद्रास्फीति तक पहुंचता है। ऐसे समय में किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक जोखिम को बढ़ा सकती है, इसलिए ऊर्जा आपूर्ति का बहुस्रोतीकरण और वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग आर्थिक नीति के स्थायी हिस्से बनने चाहिए। इसी सोच का विस्तार निर्यात बाजारों तक होता है।

कहना होगा कि भारत के लिए अमेरिका अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। वहां भारतीय दवाइयों, वस्त्रों, रत्न एवं आभूषणों तथा विभिन्न विनिर्मित वस्तुओं की मांग भारतीय उद्योगों और रोजगार से सीधे जुड़ी हुई है। उसका असर उत्पादन केंद्रों, छोटे उद्यमों, श्रमिकों और स्थानीय अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है।यहीं से निर्यात विविधीकरण का महत्व सामने आता है। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ के नाम पर भारत समेत दुनिया के देशों पर अपना दबाव बनाना जारी रखा है, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भारत अपने लिए अधिकतम निर्यात के अवसर तलाशे।

इस सबंध में जैसा कि ज्ञात है, यूरोपीय संघ उच्च मूल्य वाले बाजारों के लिए अवसर देता है। आसियान भौगोलिक निकटता और विनिर्माण संपर्क के कारण महत्वपूर्ण है। खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के अवसर खोलता है। अफ्रीका तेजी से उभरता उपभोक्ता बाजार है, जबकि लैटिन अमेरिका भारतीय ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-रसायन और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है। वस्तुतः इस विविधता का उद्देश्य किसी एक बाजार से दूरी बनाने के स्थान पर भारतीय व्यापार को कई बाजारों में फैलाना है, ताकि किसी एक क्षेत्र में आया झटका पूरे निर्यात ढांचे को प्रभावित करने की स्थिति तक पहुंच सके। भारत के लिए ब्रिक्स भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण आर्थिक मंच है। ब्रिक्स देशों के बीच माल व्यापार दो दशकों में 13 गुना बढ़कर 1.17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अब आवश्यकता ऐसे सहयोग की है, जो घोषणाओं से आगे बढ़कर सीमा शुल्क सुधार, व्यापार वित्त, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल दस्तावेजीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में छोटे उद्यमों की भागीदारी तक पहुंचे।यहां भारत के एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका निर्णायक भी हो सकती है। जिसमें कि भारत वैश्विक बाजार की दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है।

इस मामले में हमें चीन से सीखना चाहिए, जो अपने उद्योगपतियों को विदेश में सफल होने, उनके माल को विश्व के 192 देशों तक पहुंच बनाने के लिए अलग से अनेक प्रयास करता है। हालांकि भारत भी इस दिशा में गे बढ़ रहा है, किंतु उसकी वैसी आक्रामक शैली नहीं, जैसी चीन अपनाए हुए है, इसलिए भारत की वैश्विक आर्थिक क्षमता का वास्तविक विस्तार तब होगा, जब छोटे और मध्यम उद्यम अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थायी भागीदार बनेंगे। वित्त, तकनीक, बाजार और प्रमाणन से जुड़ी बाधाओं को घटाकर उन्हें वैश्विक उत्पादन नेटवर्क से जोड़ना जरूरी है। इससे रोजगार, निर्यात और स्थानीय उत्पादन क्षमता तीनों को मजबूती मिल सकती है।

इसके साथ तकनीक भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा का केंद्रीय आधार बन रही है। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल भुगतान, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षमता को वैश्विक साझेदारियों से अधिक से अधिक जोड़ा जाना चाहिए। कुछ प्रयास पिछले दिनों शुरू भी हुए हैं, किंतु वास्तविकता में वह संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं। आज भारत के सामने अमेरिका, यूरोपीय संघ, आसियान, खाड़ी, जी20, क्वाड और ब्रिक्स जैसे अनेक मंच हैं। इन सभी के साथ संबंधों को परस्पर विरोधी खांचों में देखने के बजाय भारतीय हितों के अनुरूप पूरक आर्थिक अवसरों के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहां भी प्रयासों के स्तर पर हर संभव तेजी लाने की आवश्यकता है।

भारत के लिए अगला दशक इसी कसौटी पर महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बनी रह सकती है। व्यापार नीतियां बदल सकती हैं। पूंजी का प्रवाह दिशा भी कहो, बदलता हुआ दिखे। ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। वस्तुतः ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के बीच भारत की सफलता इस बात से तय होगी कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम है, इसलिए आज विकास भारत की उपलब्धि है। प्रतिस्पर्धा उसकी अगली परीक्षा है। विविधीकरण उसकी सुरक्षा है और अपने विकल्पों का विस्तार उसकी वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता होगी।

अतः यहां कहना यही है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत के लिए यही वह सोच है, जो उसे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति से आगे ले जाकर परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली आर्थिक शक्ति बना सकती है। वैसे उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार इस दिशा में प्रयास कर ही रही होगी। फिर भी देश में जो लघु और मध्यम उद्योगों के सामने बाजार प्राप्त करने की जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उनका निराकरण बेहद जरूरी है।

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 40 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा नरहोना प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 03 अक्टूबर से 07 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला विधिक सहायता अधिकारियों को मध्यस्थता की प्रक्रिया, तकनीक एवं व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर छठे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल श्री मनोज कुमार सिंह ने मध्यस्थता के महत्व पर



प्रकाश डालते हुए कहा कि विवादों के समाधान में मध्यस्थता एक प्रभावी एवं समयबद्ध प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर उनके विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशा जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल के एसीजेएम/सचिव श्री सुनीत अग्रवाल ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं इसके व्यावहारिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि



मध्यस्थता विवादों के वैकल्पिक एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से अधिकारियों को पक्षकारों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने, प्रभावी संवाद स्थापित करने तथा विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता की विभिन्न तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने में सहायता मिलेगी। वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सुमन शर्मा एवं श्री संदीप सक्सेना द्वारा मध्यस्थता की व्यवहारिक प्रक्रिया, प्रभावी संवाद, पक्षकारों की आवश्यकताओं को समझने तथा विवादों के समाधान की विभिन्न तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यावहारिक अभ्यास एवं केस स्टडी के माध्यम से मध्यस्थता की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। डॉ. अनुपमा रावत, कोर्स डायरेक्टर एवं प्रोफेसर, पब्लिक पॉलिसी, नरहोना प्रशासनिक अकादमी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अकादमी की ओर से आवश्यक सहयोग एवं व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी द्वारा आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नरहोना प्रशासनिक अकादमी, समस्त अतिथियों एवं वरिष्ठ प्रशिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

लघु उद्योग भारती के उद्यम समागम 2026 का हुआ समापन

राज्य सरकार उद्यमियों को 800 रुपये वर्ग फीट की दर से देगी अनुदान : मंत्री काश्यप

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**



सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी और विकासक को मध्यप्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान देगी।मंत्री श्री काश्यप इंदौर में शनिवार को लघु उद्योग भारती के उद्यम समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि नवीन लघु उद्योग लगाने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। सब्सिडी वितरण में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ दो माह में सब्सिडी ऑनलाइन दी जा रही है।उन्होंने लघु उद्योग भारती के कार्यो की सराहना भी की। श्री काश्यप ने कहा कि समागम चिंतन के लिए होते हैं ।लघु उद्योगों के विस्तार के लिए जाग्रति आवश्यक है जो लघु उद्योग भारती पूरी शिद्दत से कर रही हैं। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू ने कहा कि 27 राज्यों में हमारे 70 हज़ार सदस्य हैं, छोटे उद्योगों की बात करने के लिए एवं उनके हित में सरकार की नीतियों को बनवाने और उनको क्रियान्वयन करवाने में लघु उद्योग भारती योगदान दे रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी लघु उद्योग भारती का कार्य उल्लेखनीय है देश में 65 महिला इकाई स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहीं है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र,प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती की उद्यम समागम स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री समीर मुंदडा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री अतीत अग्रवाल, आरएसएस के मध्य क्षेत्र कार्यवाह श्री अशोक अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष श्री सी पी दुबे, डीआरडीओ एवं डिफेंस क्षेत्र के चीफ एडवाइजर श्री जितेंद्र सिंह सहित लघु उद्योग भारती के देश, प्रदेश और प्रांतों की समस्त जिला इकाइयों के पदाधिकारी एवं उद्यमी शामिल हुए।

वन विहार की आवाजें कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने की सहभागिता

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



वन्य-जीव सप्ताह-2026 की थीम 'जुड़े आवास, वन्य-जीवन का विकास' के अनुरूप 3 अक्टूबर 2026 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य-जीव संरक्षण, जैव-विविधता एवं पर्यावरण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा विद्यार्थियों, युवाओं एवं आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रातः 8 से 9:30 बजे तक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 'वन विहार की आवाजें' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 81 दिव्यांग विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री सुनील सिन्हा, सेवानिवृत उप वन संरक्षक, डॉ. संगीता राजगीर, मो. खालिक एवं श्री संकल्प किसनानी द्वारा विद्यार्थियों को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक परिवेश एवं वन्य-जीवों से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रकृति भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को वन क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों, पक्षियों तथा वन्य-जीवों के प्राकृतिक आवास के संबंध में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को प्रकृति को नजदीक से देखने, वन्य-जीवों की गतिविधियों को समझने तथा प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की विशेषता अनुभवात्मक एवं समावेशी सहभागिता रही। विद्यार्थियों को वन क्षेत्र में दिखाई देने वाले पक्षियों की आवाजों, प्राकृतिक ध्वनियों एवं आसपास के जैव-विविधतापूर्ण वातावरण से परिचित कराया गया तथा भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को वन्य-जीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, प्रकृति के संरक्षण तथा वन क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान डॉ. रूही हक द्वारा किया गया।

त्योहारी सीजन में वलसाड-दानापुर-वलसाड स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार एवं समय-सारणी में संशोधन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

रेल यात्रियों की सुविधा तथा आगामी पूजा एवं शीतकालीन त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को क्लीयर करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 09025/09026 वलसाड - दानापुर - वलसाड साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के 08-08 फेरों में विस्तार करने तथा संशोधित समय-सारणी के अनुसार चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा हेतु चलथान एवं बारडोली स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी प्रदान किया गया है। इस स्पेशल ट्रेन का पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में आने वाले विस्तार एवं समय-सारणी का विवरण इस प्रकार हैः-



वलसाड-दानापुर-वलसाड साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (08-08 ट्रिप) गाड़ी संख्या 09025 वलसाड से दानापुर स्पेशल ट्रेन दिनाँक 05 अक्टूबर से 23 नवम्बर 2026 तक प्रत्येक सोमवार को वलसाड स्टेशन से सुबह 08:40 बजे प्रस्थान कर इटारसी रात 20:00 बजे, जबलपुर 23:40 बजे, पहुँचकर अगले दिन कटनी 01:05 बजे, सतना 02:20 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए दोपहर 12:00 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी। (08 सेवाएं) इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09026 दानापुर से वलसाड स्पेशल ट्रेन दिनाँक 06 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को दानापुर स्टेशन से दोपहर 13:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सतना 01:30 बजे, कटनी 04:20 बजे, जबलपुर 06:00 बजे, इटारसी 10:00 बजे पहुंचकर मार्ग से होते हुए रात 21:30 बजे वलसाड स्टेशन पहुँचेगी। (08 सेवाएं) कोच कम्पोजीशनः- इस गाड़ी में 01 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 03 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 12 शयनयान श्रेणी, 02 सामान्य श्रेणी एवं 02 एसएलआरडी सहित कुल 20 कोच रहेंगे। ट्रेन के हाल्टः- रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में भेस्तान, चलथान, बारडोली, नंदुरबार, धरनगांव, पालधी, भुसावल, खण्डवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी। यात्री विस्तारित सुविधा का लाभ लेते हुए स्पेशल ट्रेन के ठहराव की विस्तृत जानकारी स्टेशन, एनटीइएस या रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन रेलवे वेबसाइट रेलवन ऐप से भी प्राप्त कर सकते है।

150 हारमोनिका वादकों ने एक मंच पर दी अनूठी संगीतमय प्रस्तुति

भोपाल। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शनिवार को अनूठा संगीतमय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 150 हारमोनिका वादकों ने एक ही मंच पर एक साथ माउथ ऑर्गन बजाकर सामूहिक प्रस्तुति दी। अनेक वादकों के सुरों और तालमेल ने इस आयोजन को विशेष बनाया। एक ही मंच पर 150 हारमोनिका वादकों की सामूहिक प्रस्तुति नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रही। माउथ ऑर्गन की समवेत धुनों के माध्यम से कार्यक्रम में संगीत और सामूहिक समन्वय की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित दर्शकों ने खड़े होकर कलाकारों का अभिवादन किया। संगीत प्रेमियों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हारमोनिका वादन का ऐसा अद्भुत समन्वय देखा है।

विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता अभियान



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

अभियान 6.0 के अंतर्गत 03 अक्टूबर 2026 को भोपाल मंडल की रेलवे कॉलोनियों भोपाल, बीना, गुना, हबीबगंज, नर्मदापुरम, विदिशा एवं हरदा में चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रेलवे आवासों के आसपास के क्षेत्रों, कॉलोनी की नालियों, सामुदायिक स्थलों तथा कचरा संग्रहण केंद्रों की सफाई कराई गई। इसके साथ ही रेलवे कॉलोनियों में निवासरत लोगों को स्रोत पर कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करने के लिए घर-घर जाकर संपर्क किया गया तथा चार प्रकार के कचरे के पृथक्करण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। रेल प्रशासन द्वारा रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा नागरिकों की सहभागिता से स्वच्छ रेलवे कॉलोनियों का निर्माण करना है।

रानी कमलापति से गया, रीवा एवं दानापुर के लिए तीन जोड़ी विशेष ट्रेनों की आगामी सेवाएं उपलब्ध

दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा पर्व पर यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं अतिरिक्त यात्री मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल द्वारा रानी कमलापति स्टेशन से गया, रीवा एवं दानापुर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन अतिरिक्त रेल सेवाओं से यात्रियों को विभिन्न प्रमुख शहरों के बीच आवागमन के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे तथा नियमित ट्रेनों में यात्री भार कम करने में सहायता मिलेगी। आगामी परिचालन तिथियों के अनुसार विशेष ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः- 1. रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति-गया स्पेशल का आगामी फेरा 07 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। यह ट्रेन रानी कमलापति से 15:20 बजे प्रस्थान कर नर्मदापुरम 16:34 बजे एवं इटारसी 17:05 बजे पहुंचेगी तथा अगले दिन 14:30 बजे गया पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01662 गया-रानी कमलापति स्पेशल का आगामी फेरा 05 एवं 10 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। यह ट्रेन गया से 15:30 बजे प्रस्थान कर इटारसी 14:05 बजे एवं नर्मदापुरम 14:43 बजे होते हुए 16:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। इस ट्रेन के ठहराव नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर,



प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर होंगे। 2. रानी कमलापति-रीवा पूजा स्पेशल गाड़ी संख्या 02191 रानी कमलापति-रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट पूजा स्पेशल के आगामी चार फेरे 17 एवं 24 अक्टूबर तथा 07 एवं 14 नवंबर 2026 को निर्धारित हैं। यह ट्रेन रानी कमलापति से रात 22:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 07:20 बजे रीवा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02192 रीवा-रानी कमलापति साप्ताहिक सुपरफास्ट पूजा स्पेशल के चार फेरे निर्धारित हैं। यह ट्रेन रीवा से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात 21:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर एवं सतना स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी के कुल 22 कोच उपलब्ध रहेंगे। गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति-दानापुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को 12 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन रानी कमलापति से दोपहर 14:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 09:15 बजे दानापुर पहुंचेगी। इस दिशा में कुल 11 सेवाएं संचालित होंगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01668 दानापुर-रानी कमलापति द्वि-साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को 13 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन दानापुर से सुबह 11:20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 10:50 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। इस दिशा में भी कुल 11 सेवाएं संचालित होंगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में रानी कमलापति, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी जंक्शन, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

संक्षिप्त समाचार

जी -20 में भारत की दो टूक, डब्ल्यूटीओ के नियमों से ही चलेगा व्यापार

नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में ज्ञ-20 के वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में यह आरोप खारिज किया कि भारत में कुछ सेक्टरों में जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है,

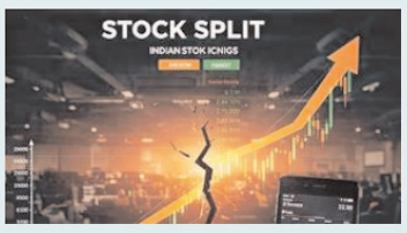


जिससे किसी दूसरे देश के उद्योगों के हितों को नुकसान पहुंच सकता हो। गोयल ने कहा कि भारत अपने आप में विशाल देश है और अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ यह वैश्विक स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन और सप्लाई चेन का दायरा बढ़ाना एक वाजिब मकसद है, लेकिन इसकी आड़ लेकर नियमों से बाहर के कदम नहीं उठाए जा सकते हैं और विकासशील देशों पर बोझ नहीं डाला जा सकता है।गोयल की यह बात इस मायने में अहम है कि अमेरिका की अगुवाई में ज्ञ-20 में यह मुद्दा उठाया गया। साथ ही अलग से अमेरिका अपने सेक्शन 301 के तहत यह जांच कर रहा है कि भारत सहित 60 देशों में स्टील, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स सहित कुछ सेक्टरों में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता होने से अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है या नहीं।

भारत की दलील

गोयल ने कहा, 'जी-20 प्रेसिडेंसी ने जिन सेक्टरों को चिन्हित किया है, उनमें भारत के पास स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी नही है।' पीयूष गोयल ने कहा कि कई देशों ने यह चिंता जताई है कि कुछ देशों में अपने हितों को बढ़ावा देने की हरकतों से डंपिंग और कम दाम पर माल दूसरे देशों में उतारने की स्थिति बन सकती है और भारत की भी ऐसी ही चिंता है।अमेरिका के टैरिफ दबाव और भारत समेत 60 देशों में 'ओवरकैपेसिटी' की जांच के बीच गोयल ने ज्ञ-20 बैठक में भारत पर लगे आरोप को खारिज किया।

3 कंपनियों के शेयरों का होने जा रहा है बंटवारा, इसी हफ्ते हुआ ऐलान



नईदिल्ली, एजेंसी। तीन कंपनियों के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। इन कंपनियों ने इसी हफ्ते स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि यह तीन कंपनियों कौन सी हैं। कितने टुकड़ों में इनके शेयरों को बांटा जाएगा।

इस कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर इस स्टॉक की कीमत 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 92.63 रुपये थी। कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा था। बता दें, पिछले एक साल में शेयरों का दाम 43 प्रतिशत बढ़ चुका है।

कंपनी के शेयरों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों का दाम घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 30 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम 30 अक्टूबर को कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही स्टॉक स्प्लिट का लाभ मिलेगा।गुरुवार को इस कंपनी के शेयरों में भी लोअर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में स्टॉक की कीमत 363.85 रुपये के स्तर पर आ गया था।

महंगाई बहुत बढ़ गई है 45 लाख में अफोर्डेबल हाउस नहीं बन सकता

कोलकाता, एजेंसी। सरकार ने सबको छत दिलवाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की नीति बनाई है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जमीन एवं मकान बनाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सात साल पहले बनी नीति अब बेमानी हो चुकी है। इसलिए देश के रियल एस्टेट डेवलपर्स चाहते हैं कि इस नीति में बदलाव हो। यही नहीं, सरकार अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा में भी बदलाव करे। वे चाहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत में कोई कैपिंग नहीं हो। अभी इसमें 45 लाख रुपये की कैपिंग है।

क्रेडाई ने की है मांग

भारत में 13,000 से भी अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन्स इसका इन दिनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता में हो रहा है। इसी दौरान क्रेडाई के प्रेसिडेंट शेखर पटेल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा बदले। उनका कहना है कि साल 2029 में जो तय हुआ था कि 45 लाख रुपये तक की कीमत के मकानों को ही अफोर्डेबल हाउस माना जाए, उसे हटाना होगा। क्योंकि जिस हिसाब से जमीन की कीमत बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल महंगा हो रहा है, इतने में मकान बनाना संभव नहीं है।

सीआरईडीएआई ने सरकार से यह रखी मांग



मानदंड में सिर्फ आकार शामिल हो

पटेल का कहना है कि इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग की नीति में मकान का आकार और मकान की कीमत, दोनों को मानक बनाया गया है। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि वह मकान की कीमत की सीमा हटा दे। अफोर्डेबल हाउसिंग में सिर्फ निर्धारित आकार को ही मानदंड बनाया जाए। इस समय देश मे सात मेट्रोपोलिटन शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले मकान और अन्य इलाकों में 90 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले मकानों को इस श्रेणी में रखा गया है। साथ ही उन मकानों की कीमत में 45 लाख रुपये की ऊपरी सीमा या कैपिंग भी तय की गई है। इससे अधिक कीमत के मकानों को

क्रेडाई ने यह सुझाव दिया

उनका तो कहना है कि मेट्रोपोलिटन सिटीज के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा और अन्य शहरों के लिए 90 वर्ग मीटर बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने क्षेत्रफल में आराम से सस्ते मकान तैयार हो सकत हैं। इसलिए आगे की नीति में भी इस आकार को बनाए रखने का क्रेडाई ने सुझाव दिया है। लेकिन कीमत सरकार कीमत को शामिल नहीं करे। वह बाजार पर छोड़ दे।

इस नीति को अंतिम रूप देने में लगेगा समय

सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की नीति में संशोधन में हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी इनवोलमेंट है। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को जीएसटी से छूट मिली हुई है। यदि इसकी सीमा में कोई बदलाव होता है तो उसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ साथ जीएसटी काउंसिल की भी अनुमति की दरकार होगी। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य सरकारों की भी भागीदारी होती है। उनका कहना है कि यदि सरकारी स्तर पर सहमति बनती है तो इसकी घोषणा आगामी बजट में हो सकती है।

जितनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी तेजी से निपटेगा देश का कर्जः ट्रंप

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। समस्या यह है कि अमेरिका का कर्ज ऐसे समय बढ़ रहा है जबकि उसकी इकॉनमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समस्या से निपटने का तरीका बताया है। उनका कहना है कि महंगाई का एक खास लेवल देश के कर्ज को बहुत तेजी से चुकाने में मदद कर सकता है।



ट्रंप ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझे पता है कि मैं दुनिया में सबसे बेहतर हूं। कर्ज चुकाने के और भी तरीके हैं। लेकिन एक तरीका यह है कि ग्रोथ के जरिए इसे चुकाया जाए और ऐसी ग्रोथ हमने पहले कभी नहीं देखी।' उन्होंने कहा कि भले ही पहले कम ब्याज दरों की वजह से उधार लेना सस्ता था, लेकिन मौजूदा समय में ऊंची ब्याज दरों के कारण सरकार कर्ज के बोझ से निपटने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है।

नोएल टाटा ने मांगा टाटा संस की मीटिंग का वीडियो, चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर सवाल उठाए



नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप में अब लेटर वॉर शुरू हो गया है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच ने हाल में एकदूसरे को कई पत्र लिखे हैं। ताजा घटनाक्रम में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा संस बोर्ड को पत्र लिखकर 17 सितंबर की मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग और मिनट्स की जानकारी मांगी है। इस मीटिंग में एन चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला लिया गया था।

नोएल टाटा ने 30 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड को यह पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने उस तरीके पर भी सवाल उठाए जिससे बोर्ड ने मीटिंग के बाद चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को सही ठहराने के लिए दो कानूनी राय पेश कीं। नोएल टाटा का कहना था कि उन्हें मीटिंग में देश के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से मिली कानूनी राय के खास बिंदुओं को विस्तार से बताने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। नोएल टाटा ने दावा किया कि प्रस्ताव को नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी की जानकारी के तौर पर पास किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि नोएल टाटा चंद्रचूड़ की रिपोर्ट के आधार पर कास्टिंग वोट और टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। उनका तर्क है कि उसके मूल कंटेंट और समय-समय पर किए गए बदलावों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

नोएल टाटा ने 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड के सामने चंद्रचूड़ की रिपोर्ट पेश की और तर्क दिया कि टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स को मिले खास वोटिंग अधिकारों को ओवरराइड करने के लिए टाटा संस के चेयरमैन के कास्टिंग वोट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को 4-1 के बहुमत से फिर से पांच साल के लिए चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया था। केवल नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। बोर्ड में ट्रस्ट के दूसरे नॉमिनी वेणु श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का समर्थन किया। यह बैठक के उस फैसले के बाद हुई थी, जिसमें उसने टाटा संस की प्राइवेट और अनलिस्टेड बने रहने की अपील को ठुकरा दिया था।

किसी डायरेक्टर के पास बोर्ड मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की पूरी कॉपी पाने का कोई असीमित अधिकार नहीं है। लेकिन सेक्रेटेरियल गाइडेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उपाय बताते हैं कि डायरेक्टर को कुछ खास रिकॉर्डिंग देखने की इजाजत दी जा सकती है ताकि वे चर्चा की पुष्टि कर सकें और फाइनल होने से पहले ड्राफ्ट मिनट्स पर कोई टिप्पणी (अगर हो तो) दे सकें।

आवश्यकता आविष्कार की जननी', डिमांड-सप्लाई का गैप पकड़ लगाया दांव, 3 साल में बनाई 3 करोड़ की कंपनी

नई दिल्ली, एजेंसी। यह कहानी है मोहिता गुप्ता इंद्रायण की। वह दिल्ली से हैं। उन्होंने डिमांड और सप्लाई के गैप को पहचानकर एक सफल फैशन ब्रांड खड़ा कर दिया है। इसका नाम 'स्प्रिंग सोल' है। साल 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। मोहिता ने इस गैप को तब महसूस किया जब उन्होंने देखा कि जहां एक ओर रेडीमेड कपड़ों में मनपसंद फिटिंग पाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर लोकल बुटीक या डिजाइनर्स के पास जाने पर जेब ढीली करनी पड़ती है। यह ब्रांड पारंपरिक भारतीय कपड़ों और जीरो वेस्ट की मिसाल बनकर 3 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर के आंकड़े को पार कर चुका है। आइए, यहां मोहिता गुप्ता इंद्रायण की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

पहला बिजनेस करना पड़ा बंद

मोहिता दिल्ली में जन्मीं और देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों में पली-बढ़ीं। कपड़ों और भारतीय विरासत से उनका पुराना नाता रहा है। लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली से अपैरल मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग की पढ़ाई की। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर साल 2010 में बच्चों के कपड़ों का ब्रांड '612 लीग' शुरू किया। यह बड़ा किड्सवियर ब्रांड बनकर उभरा। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान फिजिकल स्टोर आधारित



यह बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन, मोहिता के भीतर फैशन और भारतीय विरासत से जुड़ा कुछ नया करने की ललक कायम रही।

डिमांड-सप्लाई के इस गैप को पकड़ा

'612 लीग' के बाद मोहिता ने बाजार का गहराई से अध्ययन किया। पाया कि 5,000 से 15,000 रुपये के बीच के 'मास-प्रीमियम' सेगमेंट में बड़ा खालीपन है। ग्राहकों के पास या तो रेडी-टू-वियर के रूप में सीमित ऑप्शन थे या फिर अनिश्चित क्वालिटी वाले लोकल बुटीक। इस समस्या का समाधान निकालते हुए उन्होंने 2023 में गुरुग्राम से 'स्प्रिंग सोल' की शुरुआत की। इसका मकसद महिलाओं को बिना डिजाइनर कीमतों के उनकी पसंद के कट, डिजाइन और साइज के अनुसार कस्टमाइज्ड और सुविधाजनक कपड़े उपलब्ध कराना था।बिजनेस के शुरुआती दिनों में गुरुग्राम के यूनिट में दो दिन की बिजली कटौती के वक्त जब उत्पादन रुका और छह कारीगरों को खाली बैठा देखना पड़ा तब 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है' वाली कहावत सच साबित हुई। मोहिता ने अपने कारीगरों से बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों (कतरन) से तुर्की स्टाइल की फैब्रिक ज्वेलरी बनवाई। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते ही ये पीस रातोंरात बिक गए। इससे ब्रांड का ग्रॉस मार्जिन 15 प्रतिशत तक बढ़ गया।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट, 3 सप्ताह में निकल गए 38 अरब से ज्यादा

मुंबई, एजेंसी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह भारी गिरावट की खबर है। 25 सितंबर 2026 को सप्ताह के दौरान इसमें भी ज्यादा कमी की खबर है। एक सप्ताह में इतनी गिरावट कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें करीब .14.881 की गिरावट आई थी। उससे एक सप्ताह पहले मतलब कि 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 4.924 निकल गए थे। मतलब कि तीन सप्ताह में ही 38.148 डॉलर निकल गए। हां, 4 सितंबर 2026 तक लगातार 10 सप्ताह इसमें बढ़ोतरी ही हो रही थी।

विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 सितंबर 2026



को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में .18.343 की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें .14.881 की कमी हुई थी। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार घट कर 747.557 रहा गया है। इससे पहले 4 सितंबर 2026 को अपना विदेशी मुद्रा भंडार 785.706 के ऑल टाइम हाई पर था।

एफसीए भंडार में खूब हुई कमी

रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 25 सितंबर 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियों में .15.570 की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें .14.816 की कमी हुई थी। ताजा कमी के बाद अपना एफसीए भंडार घट कर .615.411 का रह गया है। उल्लेखनीय है कि देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आस्तियां या फॉरेन करेंसी असेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किये जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट-बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है।

जियो आईपीओ अक्टूबर के अंत में हो सकता लॉन्च! रिटेल निवेशकों के पास होगा बड़ा मौका

नईदिल्ली, एजेंसी। रिलायंस जियो के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों को इस महीने खुशखबरी मिल सकती है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का आईपीओ इस महीने या अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। आईपीओ को लेकर जियो ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार विदेश निवेशक भी इस आगामी आईपीओ में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो का आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर के दौरान खुला रह सकता है। वहीं, एंकर निवेशकों को 19 अक्टूबर को दांव लगाने का मौका मिल सकता है। बीएसई और एनएसई में कंपनी की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने की संभावना है। आईपीओ की टाइमलाइन कुछ हद तक मार्केट के मौजूदा कंडीशन पर भी निर्भर करेगा। बता दें, आईपीओ की तारीखों को लेकर जियो की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।



मामले की जानकारी रखने वाला लोगों के अनुसार जियो ने एफआईआई के साथ एक मीटिंग की है। यह मीटिंग काफी पॉजिटिव थी। इसके अलावा की तरफ से भी अच्छे संकेत लगातार मिल रहे हैं। कंपनी बाजार की मौजूदा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि, बाजार में इस मची उथल-पुथल का जियो के आईपीओ के टाइमलाइन पर असर कम पड़ने की संभावना है।

जियो ने इस साल में जून के महीने में सेबी के पास आवेदन किया था। मार्केट रेगुलेट करने वाली इस संस्था ने 28 अगस्त को आईपीओ लाने की मंजूरी कंपनी को दे दी थी।

कैसा होगा आईपीओ

जियो का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित होगा। कंपनी इश्यू से जुटाए पैसों के जरिए 27500 करोड़ रुपये के पूरा या आधा कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल करेगी। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों में कंपनी प्रयोग करेगी।इस प्रस्तावित आईपीओ मं 50 प्रतिशत हिस्सा रिटेल और हाई नेट वर्थ वाले निवेशकों के लिए रिजर्व रहेगा। बाकि पैसा इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए कंपनी रिजर्व रखेगी।

जियो आईपीओ जीएमपी

ग्रे मार्केट में फिलहाल आईपीओ को लेकर कोई हलचल नहीं है। प्राइस बैंड के ऐलान के बाद ही ग्रे मार्केट में कोई रिएक्शन दिख सकता है।

बैंकों के खिलाफ बढ़ती जा रही हैं ग्राहकों की शिकायतें, आरबीआई ने कहा सुधारें अपना सिस्टम

नई दिल्ली, एजेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में लगातार बढ़ रही ग्राहकों की शिकायतों और सिस्टम की कमियों पर सख्त रुख अपनाया है। आरबीआई ने बैंकों को अपने कामकाज और प्रोसेस में मौजूद खामियों को पहचानकर उन्हें जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए हैं। वित्त वर्ष 2025 में लोकपाल के पास शिकायतों में 13.5 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई ने इस बात पर चिंता जताई कि कई शिकायतें बैंकों के अंदरूनी लोकपाल तक पहुंचे बिना ही सीधे आरबीआई के पास पहुंच रही हैं, जिससे बैंकिंग सिस्टम के शिकायत निपटारे के ढांचे पर सवाल खड़े हो रहे हैं।



मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, पिछले महीने हुई एक बैठक में आरबीआई ने बैंकों से उन बुनियादी, प्रोसेस और कामकाज से जुड़ी कमियों की पहचान करने को कहा जिनकी वजह से शिकायतें आ रही हैं। साथ ही, बार-बार आने वाली शिकायतों की वजह का पता लगाने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने बताया कि रेगुलेटर ने ऐसे कदम उठाने और लागू करने को कहा है, जिससे इस तरह की शिकायतें बार-बार न आएं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि एक सुझाव यह भी था कि शिकायतों को सही ढंग से सुलझाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे इंडस्ट्री-लेवल के कदम उठाए जाएं। इसमें इंडस्ट्री-लेवल पर ट्रेनिंग होगी ही, साथ ही हर बैंक का बोर्ड आरबीआई के दिशानिर्देशों के हिसाब से अपनी अलग रणनीति बनाएगा।जुलाई में बैंकों और आरबीआई से जुड़े अन्य संस्थानों के इंटरनल ओम्बड्समैन की सालाना कॉन्फ्रेंस में, डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने ध्यान दिलाया कि आरबीआई लोकपाल के स्तर पर ग्राहकों के हक में सुलझाई गई शिकायतों में से एक बड़ा हिस्सा शुरू में इंटरनल ओम्बड्समैन के पास भेजा ही नहीं गया था। उन्होंने कहा, यह काफी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे इंटरनल ओम्बड्समैन फ्रेमवर्क का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। एकीकृत लोकपाल योजना जुलाई 2026 से लागू है।

मंत्री शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में मेहगांव में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन

स्वच्छ और हरित भविष्य का सपना जनभागीदारी से ही होगा साकार: कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में मेहगांव के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर एवं सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 103 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष 121 आवेदनों का संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, पूर्व मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया, एसडीएम मेहगांव सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिविर में मंत्री श्री शुक्ला ने संबल योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने जनविश्वास शिविर में कहा कि यह केवल एक दिन की औपचारिक सुनवाई नहीं, बल्कि प्रशासन को नागरिकों तक पहुंचाने की सतत पहल है। शिविर से पहले आठ दिनों तक टीमों ने घर-घर पहुंचकर समस्याएं दर्ज कीं और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की। शिविर में कुल 224 आवेदन मिले, जिनमें 103 का निराकरण किया गया, जबकि 121 प्रकरणों को कार्ययोजना में लेकर समयबद्ध समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। मंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहकर समस्याओं का समाधान करें। प्रदेश में जनविश्वास अभियान के तहत साप्ताहिक शिविरों में प्रशासनिक अमला गांवों और वार्डों तक पहुंचकर



योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देख रहा है तथा आवेदनों का मौके पर समाधान करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से सरकारी प्रयासों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। कहा कि स्वच्छ गांव, हरियाली, जल संरक्षण और ऊर्जा बचत के लिए समाज की भागीदारी जरूरी है। हर परिवार पेड़ लगाने, स्वच्छता बनाए रखने और बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण मिल सकेगा। मंत्री ने सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सोलर सहित अक्षय ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने से परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिल सकती है और पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग होगा। उन्होंने आंगनबाड़ी गतिविधियों, पोषण, स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भागीदारी का आग्रह किया। मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने स्थानीय स्तर पर धार्मिक, सार्वजनिक स्थलों और मुक्तिधाम को अतिक्रमण-मुक्त रखने, गांव को स्वच्छ बनाने और सामूहिक कार्यों में सहयोग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं की सफलता तभी बढ़ेगी, जब नागरिक भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे।कलेक्टर भिण्ड ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य है कि जो भी समस्याएँ थीं, जिनका किसी कारण से लंबे समय से निराकरण नहीं हो पाया था और जिनमें एक विभाग या दो विभाग रहते हैं, तो उन विषयों को एक ही जगह लिया जाकर उन समस्याओं का निराकरण करना है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो एक से अधिक विभागों से जुड़े हुए रहते हैं और उन विषयों को अगर दो विभाग एक साथ मिलकर देखें, तो उनका तत्काल समाधान हो जाता है। तो इस तरह के शिविर का आयोजन करने से उस प्रकार की समस्याओं का निराकरण होता है। साथ ही अलग-अलग योजनाओं में जो पंजीयन हैं, उसकी भी जानकारी और सुविधा एक ही जगह पर मिलती है।

मेहगांव क्षेत्र में किया गया आँगन मिलन सेवा कार्यक्रम किया गया



एक सत बुलेटिन, भिण्ड

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन आज परियोजना गोरमी, रौन एवं मेहगांव में किया गया। आँगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत परियोजना अंतर्गत ऑगनबाडी केन्द्रों में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया क्षेत्र अंतर्गत लाभार्थी बच्चे एवं उनके परिजन तथा सामान्य जन समुदाय उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा पौधारोपण कराया गया एवं पेड़-पोधों के संबंध जागरूकता की जानकारी से अवगत कराया गया, बच्चों के द्वारा पेंटिंग करवाई गई। ऑगनबाडी केन्द्रों में जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया, पौधारोपण कार्यक्रम कराया गया तथा बच्चों के द्वारा कहानी कविताऐं सुनाई गई। आंगन मिलन सेवा संदेश का वाचन कराया गया।

ऑगनबाडी केन्द्र पर स्वास्थ्य परीक्षण के तहत बच्चों एवं महिलाओं की प्राथमिक जाँच की गई एवं अंततः विभागीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। गधिविधियों में पोषण प्रदर्शिनी वृक्षारोपण कराया गया।

स्वस्थ और जागरूक युवा शक्ति से साकार होगा विकसित भारत का संकल्प: राजवाड़े



एक सत बुलेटिन, रायपुर

सेवा संकल्प अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कटिंदा में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं और आवश्यकताएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि शासन का उद्देश्य विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए गांवों में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने से लोगों का जीवन सुगम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीणों की समस्याओं पर संवेदनशीलता से कार्य करने और निराकरण में तत्परता बरतने को कहा। जनसंवाद के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने मुनगा का पौधा रोपकर सुपोषण का संदेश दिया। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को पौष्टिक आहार के महत्व से अवगत कराया तथा हर परिवार से अपने घर और आंगन में मुनगा लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल कर बच्चों और माताओं के पोषण को बेहतर बनाया जा सकता है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध जनभागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अधिक से अधिक मुनगा के पौधे लगाने तथा 'हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा' अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प के अनुरूप चलाए जा रहे इस अभियान के माध्यम से परिवारों को स्थानीय पौष्टिक आहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम चंद्रमेढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने युवाओं और ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग शिक्षा, खेल, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि युवावस्था जीवन को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण समय है। नशे का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार की खुशहाली, समाज की प्रगति और भावी पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित करता है।

छत्तीसगढ़ में इस मानसून 102.1% औसत बारिश दर्ज

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी 03 अक्टूबर 2026 तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून सीजन में पूरे राज्य में सामान्य से बेहतर वर्षा दर्ज की गई है। 1 जून से शुरू हुए इस वर्षा सत्र में अब तक राज्य का औसत वर्षा प्रतिशत पिछले 10 वर्षों के औसत के मुकाबले 102.1 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक औसतन 1155.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि पिछले एक दशक के आधार पर इस अवधि का सामान्य औसत 1131.1 मिलीमीटर रहा है। प्रदेश भर में बारिश का वितरण काफी विविध देखने को मिल रहा है। जहाँ एक ओर बलरामपुर जिले ने 165.3 प्रतिशत की औसत दर और 1556.6 मिलीमीटर बारिश के साथ वर्षा प्रतिशत के मामले में पूरे राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है, वहीं कुल वर्षा के परिमाण में नारायणपुर जिला 1720.2 मिलीमीटर के साथ सबसे आगे है। दूसरी ओर, राज्य के मैदानी और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपेक्षित बारिश नहीं हो पाई है, जिनमें बेमेतरा जिला महज 674.9 मिलीमीटर बारिश और 80.4 प्रतिशत वर्षा दर्ज करके सूची में सबसे निचले पायदान पर है। भौगोलिक आधार पर राज्य के विभिन्न इलाकों का हाल देखा जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ और मैदानी इलाकों के कई जिलों में बादलों ने जमकर पानी बरसाया है।

राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का राजधानी में सम्मेलन

नियमितीकरण की तर्ज पर लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग शासन के समक्ष रखने पर बनी सहमति

एक सत बुलेटिन, रायपुर

ईपीएफ, नियमितीकरण समेत विभिन्न लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ (620) का प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी सम्मेलन राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित साहू भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेशभर के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सम्मेलन में ईपीएफ की मांग को प्रमुखता से शासन के समक्ष रखने के साथ ही लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारियों ने अपनी सेवा अवधि, ईपीएफ, नियमितीकरण सहित विभिन्न समस्याओं से संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में अन्य विभागों में किए जा रहे नियमितीकरण की तर्ज पर प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में लंबे समय से



कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग शासन के समक्ष रखने पर सहमति बनी। संगठन ने विभागवार कर्मचारियों की जानकारी एकत्र कर उनकी मांगों को शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा लंबित मामलों के निराकरण के लिए चरणबद्ध प्रयास करने की बात कही। सम्मेलन में संगठन की आगामी कार्ययोजना और संगठन को मजबूत करने पर भी मंथन हुआ। कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ईपीएफ, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों को संगठित तरीके से शासन के समक्ष रखने की रणनीति पर चर्चा की गई। सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष मिलाप यादव, निशांत दुबे, कोषाध्यक्ष दीपक दशमेर, रायपुर संभाग अध्यक्ष स्वीटी चंद्राकर सहित प्रदेश के विभिन्न संभागों और जिला इकाइयों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग ने जांच समिति गठित की

एक सत बुलेटिन, रायपुर

लोक निर्माण विभाग ने राजनांदगांव-खैरागढ़ मुख्य मार्ग के नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य तथा राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में कथित गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई है। समिति निर्माण कार्यों के विभिन्न पहलुओं और शिकायत की जांच कर तीन दिनों में प्रमुख अभियंता को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच समिति में मुख्य अभियंता व्ही.एस. कोरम, अधीक्षण अभियंता राजीव नशीने तथा कार्यपालन अभियंता प्रभात सक्सेना और



सी.एस. ओगरे शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित जांच समिति राजनांदगांव-खैरागढ़ सड़क एवं राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं की किसी स्वतंत्र संस्था से उच्च स्तरीय जाँच कराने, जीएसबी, डब्लूएमएम सब-ग्रेड, डामरीकरण, बिटुमिन की मात्रा, सड़क की मोटाई, घनत्व, ग्रेडेशन, लेवल एवं अंडुलेशन सहित सभी तकनीकी मानकों की प्रयोगशाला से जांच जैसी बिंदुओं पर जांच करेगी। समिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्यपालन एजेंसी की भूमिका, जांच पूर्ण होने तक संबंधित कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने पर विचार करने, गुणवत्ता से समझौता, वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही तथा डोंगरगांव-कुमरदा सहित जिन स्थानों पर सड़क उखाड़कर छोड़ी गई है, वहां तत्काल सुरक्षित आवागमन हेतु मरम्मत, चेतावनी संकेत एवं वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों एवं नागरिकों के साथ की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर। प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 07 अक्टूबर को दुर्ग जिला मुख्यालय में सेवा ज्योति कलश यात्रा एवं 'विकसित भारत का संकल्प' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने दुर्ग जिला प्रशासन, संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं आम नागरिकों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरेन्द्र कौशिक, श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर, विनोद अरोरा, कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और



आयोजन से जुड़े नोडल विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री यादव ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने, विकसित भारत/2047 का सामूहिक संकल्प लेने तथा केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली सेवा ज्योति यात्रा को प्रशासन और आम नागरिकों के समन्वय से सफल एवं प्रभावी बनाया जाए।

'सेवा संकल्प पखवाड़ा' के तहत ग्राम कुकेरा में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह आयोजित

मोदी सरकार में गांव, गरीब, किसान और महतारियों का बढ़ा मान: बृजमोहन

एक सत बुलेटिन, रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के सफल 25 वर्ष पूर्ण होने और उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रव्यापी 'सेवा संकल्प पखवाड़ा' के अंतर्गत रायपुर लोकसभा क्षेत्र के धरसीवां विधानसभा के ग्राम कुकेरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, दवा वितरण तथा स्वच्छता दीदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सांसद ने उपस्थित जनसमुदाय को स्वच्छता संकल्प की शपथ भी दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का हर क्षण देश और जनता की सेवा में समर्पित किया है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और दुश्मनों को घर में घुसकर जवाब देने का साहस मोदी सरकार ने दिखाया है। ' श्री अग्रवाल ने केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि 'महतारी वंदन योजना' से माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये सीधे खाते में देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाया गया है। प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान खरीद कर देश में सबसे अधिक



सम्मान किसानों को दे रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को बीमारी के समय संबल देने के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज (आयुष्मान भारत), हर गरीब के सिर पर पक्की छत के लिए प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त राशन और घर-घर नल से जल जैसी मूलभूत सुविधाएं सीधे जनता तक पहुंच रही हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रोके गए विकास कार्यों और आवास निर्माण को डबल इंजन की सरकार ने पुनः गति दी है। कुकेरा व नवापारा क्षेत्र में पेयजल की समस्या पर उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद ने स्वच्छता दीदियों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि समाज को स्वस्थ और स्वच्छ रखने में स्वच्छता दीदियों का योगदान अतुलनीय है। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे ग्रामीणों का चेकअप कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं तथा सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगलकामना की।बी इस अवसर पर पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, कृष्ण कुमार वर्मा, भरत सोनी, केदार वर्मा, पुरुषोत्तम साहू, बिरजू साहू, बलराम साहू, देवेंद्र, जिया वर्मा, किरण साहू, हीरा वर्मा, रानी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे।

अब तक गुजरात के एकतानगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाने वाले पर्यटकों के लिए नर्मदा नदी में चलेगा क्रूज !

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से स्टैच्यू ऑफ वननेस को जोड़ेगा, एक बार में बैठेंगे 600 यात्री

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



600 यात्रियों की क्षमता वाला नया लग्जरी क्रूज

अब तक गुजरात के एकतानगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाने वाले पर्यटकों के लिए नर्मदा नदी में क्रूज का सफर एक अलग आकर्षण रहा है। लेकिन आने वाले समय में यही नदी एक ऐसी यात्रा का रास्ता बन सकती है, जो गुजरात को मध्य प्रदेश से जोड़ देगी। अगर यह सेवा शुरू होती है, तो पर्यटकों को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर तक नर्मदा के रास्ते यात्रा करने का नया विकल्प मिलेगा। एकतानगर से ओंकारेश्वर तक नर्मदा पर क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी है। इस क्रूज को 597 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ओंकारेश्वर में 108 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस तक ले जाने का प्रस्ताव है। एकतानगर से ओंकारेश्वर तक नर्मदा क्रूज सेवा की योजना जरूर तैयार है, लेकिन इसे अभी अंतिम रूप से शुरू नहीं किया गया है। जरूरी वैधानिक और सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही क्रूज का संचालन शुरू हो सकेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी के एडिशनल कलेक्टर नारायण मधु के मुताबिक, 600 यात्रियों की क्षमता वाला नया लग्जरी क्रूज पहले ही एकतानगर में नर्मदा नदी पर अपनी सेवाएं दे रहा है। मंजूरी मिलने के बाद इसी क्रूज को प्रस्तावित रूट पर चलाया जा सकता है। इस क्रूज को सिर्फ आने-जाने के सफर के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन और कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्रूज में करीब 250 मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था और एक परफॉर्मेंस डेक भी है। यानी योजना सिर्फ कुछ घंटों की नदी यात्रा तक सीमित नहीं है। इसे लंबी दूरी के पर्यटन अनुभव के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। एकतानगर में पर्यटकों के लिए पहले से कई आकर्षण मौजूद हैं। अब इनके साथ कुछ नए आकर्षण भी जोड़े जा रहे हैं। इनमें डैम एक्सपीरियंस सेंटर, वाटर पार्क, फॉरेस्ट म्यूजियम और गुजरात वंदना म्यूजियम शामिल हैं। इसके अलावा म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, म्यूजियम ऑफ द रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया और वीर बालक उद्यान भी विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का मकसद पर्यटकों को सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सीमित रखने के बजाय एकतानगर में ज्यादा समय बिताने के लिए आकर्षित करना है। करीब 56 वर्ग किलोमीटर में फैला एकतानगर लगभग 90 गांवों को कवर करता है। यहां 26 बड़े पर्यटन आकर्षण हैं और हर साल 50 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए यहां 55 इलेक्ट्रिक बसों के साथ ई-रिक्शा, ई-कार्ट और ई-बाइक जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इनसे कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अगर नर्मदा में इंटरस्टेट क्रूज सेवा शुरू होती है, तो इससे एकतानगर के पर्यटन को गुजरात से बाहर मध्य प्रदेश तक जोडऩे का नया रास्ता भी बन सकता है। एकतानगर में पर्यटन बढऩे का असर स्थानीय रोजगार पर भी पड़ा है। करीब 1,800 आदिवासी महिलाओं को सीधे रोजगार मिला है, जबकि करीब 7,000 लोग अप्रत्यक्ष तौर पर पर्यटन से जुड़े काम कर रहे हैं। इनमें हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और दूसरी पर्यटन सेवाओं से जुड़े काम शामिल हैं।

भोपाल में फिर शुरू होगी सीलिंग की कार्रवाई

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



भोपाल के रिहायशी इलाकों में दुकानें, शोरूम और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों के लिए नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई फिर चिंता बढ़ा सकती है। करीब एक महीने से रुकी कार्रवाई को दोबारा शुरू करने के लिए निगम नई कार्ययोजना तैयार कर रहा है। इस बार सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि किस प्रतिष्ठान पर सीलिंग की कार्रवाई होगी और किसे नियमों के तहत कारोबार जारी रखने का मौका मिल सकता है। निगम के अधिकारी मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में प्रस्तावित प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखकर आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। फिलहाल कार्रवाई शुरू करने की निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर भुवन गुप्ता के मुताबिक, नए ड्राफ्ट मास्टर प्लान के प्रावधानों के आधार पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में विकसित रिहायशी इलाकों में पहले से चल रही कुछ गैर-रिहायशी गतिविधियों को निर्धारित शर्तों और शुल्क के साथ नियमित करने का प्रस्ताव है। ऐसे प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की संभावना हो सकती है, जो ड्राफ्ट जारी होने से पहले से संचालित थे और नियमितीकरण की पात्रता पूरी करते हैं। गैर-रिहायशी दरों पर जमा प्रॉपर्टी टैक्स और गैर-रिहायशी इस्तेमाल के बिजली कनेक्शन जैसे रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। हालांकि, केवल पुरानी दुकान होने से नियमितीकरण का अधिकार नहीं मिल जाएगा। संबंधित प्रतिष्ठान को सडक़ की चौड़ाई, पार्किंग और अन्य लागू नियमों की शर्तें भी पूरी करनी होंगी। ड्राफ्ट में कुछ श्रेणियों को नियमितीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है।

स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक : राज्यमंत्री गौर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने विद्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में सहभागिता कर श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संवर्धन और अपने परिवेश की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का सामूहिक एवं नैतिक दायित्व है। सार्वजनिक स्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छ, निर्मल और हरा-भरा बनाए रखने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, स्वास्थ्य शिविर के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं बड़ी संख्या में गणमान्य स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने रेखांकित किया कि सेवा संकल्प अभियान का मूल ध्येय जनसेवा के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। श्रीमती गौर शनिवार को मिसरोद स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। शिविर में नोबल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा स्थानीय नागरिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने शिविर का अवलोकन किया और उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य जांच प्रक्रियाओं एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने तथा नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने विद्यालय प्रांगण में

त्यौहारो के दौरान सुरक्षा बनाये रखने बढ़ाई जायेगी नाईट पैट्रौलिंग

भोपाल। आगामी दिनो में नवरात्र से लेकर दशहरा और दिवाली तक शहर में बढ़ने वाली भीड़ और देर रात तक होने वाली पारिवारिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने नाईट पैट्रोलिंग बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। रात के समय होने वाली अपराधिक वारदातो पर लगाम लगाने के लिये पुलिस लाइन और अलग-अलग कार्यालयों में अटैच जवानों को रात के समय सड़कों पर उतारा जाएगा। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलने वाली गश्त में आरक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक, एसआई, निरीक्षक और एसीपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के निर्देश पर चारों जोन के हिसाब से ड्यूटी चार्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिये ऐसे थाना क्षेत्रों और स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां बीते दिनो चोरी, लूट, मोबाइल झपटमारी और चाकूबाजी जैसी घटनाएं ज्यादा हुई हैं।

स्वच्छता ही सेवा-2026 के संदेश को SBI ने दिया सम्मान और संवेदना का स्वरूप

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



स्वच्छता केवल साफ-सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ समाज, सम्मानजनक जीवन और जिम्मेदार नागरिकता की पहचान है। इसी व्यापक भावना को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल मंडल द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा-2026' अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार की जनकल्याणकारी पहलों को जनभागीदारी से जोड़ने में सदैव सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इसी क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में उन कर्मठ सफाई कर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की गई, जो प्रतिदिन समाज को स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को 'समाज के सच्चे नायक' के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही, उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। जो लोग निरंतर दूसरों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने में जुटे रहते हैं, उनके स्वास्थ्य, सम्मान और गरिमा की चिंता करना भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल मंडल के प्रमुख श्री प्रभाष कुमार सुबुद्धि ने सफाई कर्मियों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि वे समाज के ऐसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिनका कार्य प्रतिदिन हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों का सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके अमूल्य योगदान के प्रति सामूहिक कृतज्ञता और संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि स्वच्छता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होता है, जब उसमें स्वच्छता के साथ संवेदनशीलता, सम्मान और सहभागिता भी शामिल हो। स्वच्छ समाज का निर्माण केवल सफाई कर्मियों के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदार भागीदारी से संभव है। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हैवी व्हीकल चलाने वाले ड्रायवरो और कंडक्टरो दी जायेगी ट्रैनिंग

भोपाल। प्रदेश में बस हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार निजी बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को फ्री ट्रैनिंग देगी। बताया गया है की बीते समय हुए हादसो में चालको ओर कंडक्टरो की ट्रेनिंग में यह बात सामने आई थी, कि हादसे के बाद ड्राइवर कंडक्टर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार नहीं होते। बस में आग लगने, अचानक ब्रेक फेल होने या तकनीकी खराबी पर कई बार वाहन संभालने के बजाय चालक भाग जाते हैं। इससे यात्रियों की मुश्किल बढ़ने के साथ जनाक्रोश की स्थिति बनती है। आपात स्थिति संभालने के लिए भी ड्राइवरों के पास व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं है। अब सुगम परिवहन सेवा के तहत इन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिफेंसिव ड्राइविंग, स्पीड जजमेंट, आपात स्थिति में वाहन नियंत्रित करने और यात्रियों से व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआत 85 हजार निजी बस ड्राइवरों और 55 हजार से अधिक कंडक्टरों से होगी। इसके लिए प्रदेश में 38 नए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, छतरपुर और बैतूल में पांच रीजनल ड्राइविंग सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा 33 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। इनमें 11 सेंटर के प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिए हैं, जबकि 22 की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।



हास्य, रहस्य और रंगमंचीय कौशल से सजी सिंधी नाट्य प्रस्तुतियां

भारत भवन में चतुर्थ अखिल भारतीय सिंधी समारोह का शुभारंभ

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



बहुकला केंद्र भारत भवन में शनिवार को चतुर्थ अखिल भारतीय सिंधी नाट्य समारोह का शुभारंभ हुआ। भारत भवन और सिंधी साहित्य अकादमी के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय समारोह सुंदर अगनानी की स्मृति को समर्पित है। सिंधी रंग समूह, भोपाल के संयोजन में आयोजित इस समारोह के पहले दिन हास्य, रहस्य और पारिवारिक संबंधों की उलझनों को अभिव्यक्त करती दो नाट्य प्रस्तुतियों 'मिस्टर एंड मिसेस बोलना...नी' और 'ही छा थी व्यो' का मंचन किया गया। इसके साथ ही 'सुंदर अगनानी : फन-ए-शख्सियत' शीर्षक वृत्तचित्र के प्रदर्शन ने दिवंगत रंगकर्मी की स्मृतियों को पुनः जीवंत किया। समारोह की पहली प्रस्तुति 'मिस्टर एंड मिसेस बोलना...नी' ने मध्यमवर्गीय दांपत्य जीवन की सहज नोक-झोंक को हास्य और रोमांच के रंगों में प्रस्तुत किया। दीपक वाघमारे लिखित इस नाटक का निर्देशन जय पंजवानी ने किया है। पति-पत्नी के बीच होने वाली रोजमर्रा की तकरार से शुरू होने वाली कहानी उस समय नया मोड़ लेती है, जब घटनाक्रम में एक चोर की एंट्री होती है। इसके बाद रिश्तों में विश्वास, धैर्य और परिस्थितियों से उपजने वाला तनाव कहानी को रहस्य और रोमांच से जोड़ता है। नाटक की विशेषता हास्य और थ्रिल का संतुलित मेल रहा। अप्रत्याशित घटनाओं और बदलती परिस्थितियों ने कथा को रोचक बनाए रखा। मध्यमवर्गीय जीवन से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुति ने दर्शकों को परिचित सामाजिक परिवेश से जोड़ा।

ग्राम पंचायत अर्रावती उपचुनाव में सुनील मेहर सरपंच निर्वाचित

बैरसिया। बैरसिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अर्रावती में रिक्त सरपंच पद का निर्वाचन शासन के नियम अनुसार 29 सितंबर 2026 को उप चुनाव ईवीएम मशीनों से संपन्न कराया गया था। इस ग्राम पंचायत में कुल 1246 मतदाता है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पद हेतु 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। ओर 854 मतदाताओं ने वोट डाले थे। शनिवार को निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार आदित्य कुमार जगेला ने सभी प्रत्याशियों के समक्ष मतों की काउंटिंग की गई। काउंटिंग में सर्वाधिक मत 441 सुनील कुमार मेहर (सोनू) ने प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंद्वी को 102 मतों से पराजित कर जीत हासिल की , निर्वाचन अधिकारी ने सुनील कुमार मेहर को विजय घोषित करते हुए सरपंच का प्रमाणपत्र सौप दिया। आपको बता दें की अर्रावती पंचायत में वित्तीय अनिमित्तताओ की जांच के चलते सरपंच को पद से पृथक हो जाने के कारण पद रिक्त था।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के राष्ट्रसेवा के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का किया आह्वान

सेवा संकल्प अभियान के सेवा यात्रियों का मंत्री उईके ने किया स्वागत

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी की सेवा संकल्प यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के सिंगरौली जिले के निगरी पहुंचने पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने सेवायात्रियों का उत्साहवर्धन करते हुए सेवा, समर्पण, स्वच्छता और जनभागीदारी के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रभारी मंत्री श्रीमती उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की यात्रा के रूप में महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया है। सेवा संकल्प अभियान इसी सेवा भावना और सामाजिक दायित्व के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सेवायात्रियों से उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं तथा नागरिकों को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करें। प्रभारी मंत्री श्रीमती उईके ने स्वच्छताकर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सेवा और स्वच्छता के कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। निगरी में सेवा यात्रियों के स्वागत के लिए सांसद सीधी-सिंगरौली डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक धौहनी श्री कुंवर सिंह टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने सेवा यात्रियों का स्वागत किया और सेवा, स्वच्छता तथा जनभागीदारी की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

हम अयोग्य हैं तो हमारे पढ़ाए डॉक्टर-इंजीनियर भी अयोग्य

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और सेवा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। डॉ. अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 1998 से सेवा कर रहे शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में लाना उनके लिए बड़ा सवाल है। शिक्षकों का कहना है कि यदि वे अयोग्य थे तो सरकार ने 28 साल पहले उनकी नियुक्ति क्यों की और इतने वर्षों तक उनसे बच्चों को पढ़ाने का काम क्यों कराया। शिक्षक संगठन के परशुराम कपाडिया ने कहा कि आंदोलन में बैठे शिक्षक अपने निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उन साथियों के दर्द को लेकर संघर्ष कर रहे हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके अनुसार, 1998 की नियुक्ति को बाद में 2018 मानने से करीब 20 साल की सेवा अवधि शून्य हो गई। इसका असर सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले ग्रेच्युटी, पेंशन और अर्जित अवकाश जैसे लाभों पर पड़ा है। कपाडिया ने कहा कि कई शिक्षकों ने करीब 25 साल सेवा करने के बाद भी ऐसी आर्थिक स्थिति देखी है कि कुछ को मजदूरी तक करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति देखकर शिक्षक संगठन ने तय किया कि जब तक वे सामने हैं, तब तक अपने साथियों के दर्द के लिए आवाज उठाई जाए।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अमित शर्मा** द्वारा प्रकाशन स्थल बी-9 विवेक विहार कॉलोनी, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474001 से प्रकाशित एवं सर्वोदय ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, नया बाजार केनरा बैंक के पास ग्वालियर (म.प्र.)-474001 से मुद्रित। स्थानीय संपादक राजीव शुक्ल* पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI - MPHIN/2019/79098/ E-mail: EKSATBULLETIN@GMAIL.COM, WWW.EKSATBULLETIN.IN, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088